

BOKARO STEEL PLANT

4311. **SHRI HARDYAL DEVGUN:** Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to state:

(a) the total expenditure incurred so far in levelling the ground for Bokaro Steel Plant; and

(b) who are the owners of the land adjoining the present site of Bokaro Steel Plant?

THE MINISTER OF STEEL, MINES AND METALS (DR. CHANNA REDDY):

(a) An expenditure of Rs. 82.72 million has been incurred on site levelling upto the end of January, 1968.

(b) The information of this nature is not being maintained.

AGREEMENTS ON FOREIGN COLLABORATIONS

4312. **SHRI S. C. SAMANTA:** Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) the names of countries with which agreements have been arrived at for Indian collaboration in setting up plants, factories etc.,

(b) the names of industries for the setting up of which Indian collaborations have been agreed to;

(c) the percentage of profits of produced goods which will be transferable to India under agreement; and

(d) the salient features thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) No agreement with any foreign country has been concluded by the Government of India for Indian collaboration setting up plants, factories etc.

(b) to (d). Do not arise.

EXPORT OF PASSENGER COACHES AND WAGONS

4313. **SHRI S. C. SAMANTA:** Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) the foreign earnings in the export of passenger coaches and wagons manufactured in India during the year 1967-68 and the expected earning during 1968-69;

(b) whether railway engines, including the electric railway engines are also exported; and

(c) if so, the number of locomotives exported during the current year and their commitments for 1968-69?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) Export of railway wagons coaches during the year 1967-68 (April-December, 1967) amounted to Rs. 55.46 lakhs. An export target of Rs. 7.50 crores has been fixed for the year 1968-69.

(b) and (c). So far there has been neither any export of engines including electric locomotives nor any export order received.

कोयला विकास निगम के साथ समझौता

4314. **श्री महाराज सिंह भारती :**
श्री शिवचरण साल :

क्या रेलवे मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आठ वर्ष तक पल व्यवहार करने के बाद भी रेलवे विभाग का राष्ट्रीय कोयला विकास निगम से समझौता नहीं हो सका है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उक्त निगम द्वारा रेलवे को जिन दरों पर कोयला दिया जाता है उसको उनसे कम दरों पर कोयला मिल रहा है ?

रेलवे मंत्री (श्री जे० सु० पुनाचा) :

(क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

रेलवे इंजनों का आयात

4315. श्री महाराज सिंह भारती :

श्री शिव चरण लाल :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे इंजन आयात करने के मामले में विश्व में भारत का प्रथम स्थान है ; और

(ख) क्या आगामी दस वर्षों में भारत को इस मामले में आत्म-निर्भर बनाने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाबा) : (क) विश्व के हमारे सभी देशों ने कितने और कितनी कीमत के रेल इंजनों का आयात किया है, इसकी जानकारी रेल मंत्रालय को नहीं है । ऐसी स्थिति में, यह बताना सम्भव नहीं है कि रेल इंजनों के आयात में विश्व में भारत का स्थान प्रथम है या नहीं ।

(ख) जी हां । देश में उत्पादन की जो क्षमता अब तक विकसित हो चुकी है उससे भाप रेल इंजनों की आवश्यकता पूरी हो जाती है । डीजल और त्रिजली रेल इंजनों के लिये भी कुछ उत्पादन क्षमता विकसित हुई है और उसका लगातार विस्तार किया जा रहा है । आशा है कि अगले 4-5 वर्षों में यातायात की किसी विशेष मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक किसी विशेष किस्म के रेल इंजन को छोड़कर रेलों की पूरी आवश्यकता के लिए पर्याप्त क्षमता उपलब्ध हो जायेगी ।

खेमी तथा तांबा परियोजना

4316. श्री महाराज सिंह भारती : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खेमी तांबा परियोजना में उपोत्पाद के रूप में गन्धक के अम्ल का उत्पादन करने का विचार है और

इसका प्रयोग रासायनिक उर्वरक तैयार करने में किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो इस उर्वरक कारखाने की कहां स्थापना की जाने की संभावना है और इसमें कितना और किस किस्म का उर्वरक तैयार होने की संभावना है ; और

(ग) समूचे परियोजना पर कितनी पूंजी लगेगी इसके कब तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है और इस काम में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) हां, महोदय ।

(ख) तांबा परियोजना के साथ प्रति वर्ष 2,14,500 टन ट्रिपल सुपरफास्फेट उर्वरक के उत्पादन के लिये खेतरी में एक उर्वरक कारखाने की स्थापना की जायेगी ।

(ग) 85.93 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले खेतरी तांबा, परियोजना समूह के 1970-71 में चालू किये जाने की सम्भावना है । यह 1972-73 तक पूरे उत्पादन तक पहुंच जायेगा । हो चुकी प्रगति का सूचक एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

1. खेतरी में खान विकास कार्य कार्यक्रम के अनुसार आरम्भ कर दिया गया है, जिस पर 617.62 लाख रुपया व्यय-साध्य है । विभिन्न स्तरों और ढलवा मेखला आदि पर 3129.50 मीटर तक खुदाई हुई है । कोलिहान खान के मुख्य रास्ते का काम भी शुरू कर दिया गया है ।

2. आर्दमियों और उपकरणों को खान में ले जाने के लिये और खान में से अयस्क के दैनिक उत्पादन को बाहर लाने के लिए दो कूपक खोदे जा रहे हैं । अभी तक उत्पादन और सेवा कूपक क्रमशः 191.21 और 130 मीटर की गहराई तक खोदे जा चुके हैं । सेवा कूपक में दो सर्बिम स्टेशन खोले जा

चुके हैं—एक 300 मीटर के स्तर पर और दूसरा 240 मीटर के स्तर पर—जिन में लगभग 80 मीटर का चालन अन्तर्गस्त है। कूपों की खुदाई के काम में तेजी लाने के लिए आवश्यक उपकरण लगाये जा चुके हैं और उन्हें चालू किया जा चुका है।

3. फ्रांसीसी कम्पनियों के एक समूह के साथ पूरे संयंत्र के चित्रण बनाने के लिये समझौता कर लिया गया है।

4. फिनलैंड की एक कम्पनी मैसर्स आयुटोकुम्पु ओइ, जिसके पास स्फुरण प्रद्रावक प्रक्रिया के संसार के एकस्व अधिकार हैं, के साथ उस प्रक्रिया के प्रयोग के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर हो गये हैं।

5. फ्रांसीसी कम्पनियों के समूह के साथ 1.16 करोड़ के मूल्य के उपकरण प्राप्त करने के लिए संविदाओं पर हस्ताक्षर हो गये हैं। अन्य बोलियों पर विचार हो रहा है और उन उपकरणों के लिये, जिनका आयात आवश्यक है, जल्दी ही आदेश दे दिये जायेंगे। सामान्य इंजीनियरिंग और सामान्य उपक्रम के बारे में भी फ्रांसीसी कम्पनियों के समूह के साथ समझौते पर हस्ताक्षर हो गये हैं। यह समझौता 30-6-67 से लागू है।

6. देश में बनने वाले उन उपकरणों की प्राप्ति के लिये जिस में अधिक समय लगता है, कार्यवाही शुरू की जा चुकी है।

7. निगम और सलाहकारों के कर्मचारियों की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 561 रिहायशी एककों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। 958 अतिरिक्त क्वार्टरों के निर्माण का काम भी हाथ में लिया जा चुका है।

8. संकेन्द्रक और संबंधित भवन निर्माण कार्यों के लिए निविदाएं मांगी गई थीं और उन पर विचार हो रहा है।

9. चीनारा और जोधपुरा को प्रतिदिन 90 लाख गैलन पानी सप्लाई करने के लिए 269 लाख रुपये की लागत की एक जल प्रदाय योजना बनाई गई है और काम में प्रगति हो रही है।

मेरठ-हापुड़ रेलवे लाइन पर चन्दसारा हाल्ट स्टेशन

4317. श्री महाराज सिंह भारती : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेरठ रेलवे हापुड़-लाइन पर चन्दसारा हाल्ट की कब व्यवस्था की गई थी और इस हाल्ट स्टेशन से इस समय प्रतिमास औसतन कितनी आय होती है ;

(ख) क्या यह सच है कि वहां का ठेकेदार खुले मैदान में टिकट जारी करता है और वहां पर टिकट घर अथवा यात्रियों के लिये कोई शंड नहीं है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि प्रत्येक गाड़ी के वहां पर पहुंचने पर ठेकेदार टिकटों पर तारीख की मोहर लगाने की मशीन और अन्य आवश्यक सामान को आधा मील दूर गांव से लाता है ; और

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त हाल्ट स्टेशन पर यात्रियों तथा कर्मचारियों के आवास के लिये कब तक प्रबन्ध करने का सरकार का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री जे० मु० पुनावा) :

(क) मेरठ-हापुड़ लाइन पर चन्दसारा हाल्ट की व्यवस्था 1929 में की गई थी। 1967 में इस हाल्ट की औसत मासिक आमदनी 1,088 रु० थी।

(ख) और (ग). जी हां।

(घ) ठेकेदार और यात्रियों के इस्तेमाल के लिए टिकट घर और प्रतीक्षालय की व्यवस्था करने के प्रश्न की जांच की जा रही है।

TEXTILE MILLS IN VIDHARBHA

4318. SHRI S. K. TAPURIAH: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that two textile mills run by Government in Vidharbha are in financial crisis;

(b) if so, the amount invested by Government in these mills since their takeover and increase/decrease in production; and

(c) the quantity of stocks lying unsold with them at present?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) No, Sir.

(b) and (c). There is no Central Government investment in these mills. Particulars of the latest position regarding investments by the State Government, increase/decrease in production and stocks lying unsold with the mills are being collected and will be placed on the Table of the House.

SCHOLARSHIP TO RAILWAY EMPLOYEES' CHILDREN

4319. SHRI CHINTAMANI PANI-GRAHI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the number of scholarships for technical education of children of Railway employees awarded in Khurda Division in 1966-67 and 1967-68 respectively from the Staff Benefit Fund;

(b) the amount spent by way of scholarships during the above period; and

(c) the list of the recipients of these scholarships for technical education?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA):

(a) Year	Scholarships
1966-67	28
1967-68	35

(b) Year	Amount spent
1966-67	Rs. 11,900/-
1967-68	Rs. 12,107/-

(c) A list is laid on the Table of the House [Placed in Library. See No. LT-503/68]

NATIONAL COAL DEVELOPMENT CORPORATION ENQUIRY COMMITTEE

4320. SHRI S. R. DAMANI: Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to state:

(a) whether the National Coal Development Corporation Enquiry Committee has submitted its interim report;

(b) if so, the main recommendations thereof;

(c) when the Committee is likely to submit its final report; and

(d) whether the Committee appointed any study group or a sub-committee for studying any aspect of the working of the National Coal Development Corporation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL, MINES & METALS (SHRI P. C. SETHI): (a) and (b). National Coal Development Corporation Enquiry Committee has submitted its First Report. The main recommendations/conclusions of the Committee are still under examination.

(c) The Committee is likely to submit its report by 30-4-68.

(d) No., Sir.

MATHUR COMMITTEE

4321. SHRI P. VISWAMBHARAN: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) the recommendations made by the Mathur Committee appointed to study the working of certain departments under his Ministry; and

(b) the recommendations which have been accepted and implemented?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) Presumably the Hon. Member is referring to the recommendations of the Study Team appointed under the Chairmanship of Shri H. C. Mathur, to examine the working of the Dte. General of Technical Development. The Study Team in its Report submitted in two parts had, in all, made 242 recommendations covering the functions and organisational pattern of the DGTD.

(b) Out of the total of 242 recommendations made, the Govt. have accepted 225 recommendations, some of which were accepted with certain modifications

126 recommendations have already been implemented. Out of the remaining accepted recommendations, apart from those which are of a general nature, the rest are under various stages of implementation.

PUBLIC SECTOR STEEL PLANTS

4322. SHRI SRADHAKAR SUPAKAR: Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to state:

(a) whether the public sector steel plants are able to meet the internal demands of iron and steel; and

(b) the percentage of the production of iron and steel which is kept for export?

THE MINISTER OF STEEL, MINES AND METALS (DR. CHANNA REDDY):

(a) No, Sir. The public sector steel plants are not able to meet fully internal demands of iron and steel. Even together with the production in the private sector, there are certain categories of steel in which the demands exceeds the total production. However, in certain other categories the internal production is in excess of the domestic demand and leaves sufficient scope for export.

(b) No percentage for exports has been earmarked as such. In the year 1966-67, the total exports of iron and steel amounted to about 0.47 million tonnes as against the total internal production of 5.5 million tonnes.

SHORTAGE OF NON-FERROUS METALS

4323. SHRI SRADHAKAR SUPAKAR: Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to state:

(a) whether there is an acute shortage of non-ferrous metals in the Country; and

(b) if so, the steps taken to carry out extensive survey for these metals?

THE MINISTER OF STEEL, MINES AND METALS (DR. CHANNA REDDY):

(a) Yes, Sir. India has been primarily an importer of Non-Ferrous Metals and is likely to continue to be so for most of these

metals except in the Case of aluminium for the production of which adequate ore reserves, viz. bauxite, exist in the country.

(b) Search for deposits of non-ferrous metals is being continued by the Geological Survey of India in several parts of the country by large scale mapping, pitting and trenching, geochemical and geophysical survey, drilling and exploratory mining. The following specific steps are being taken to increase the indigenous production on non-ferrous metals:

1. *Aluminium*: Installed capacity aluminium in the country at present is 115,800 tonnes per annum. A further capacity of 327,500 tonnes per annum (150,000 tonnes in the public sector and 177,500 tonnes in private sector) is under various stages of implementation. It is likely to take the installed capacity to 443,300 tonnes per annum by the end of the Fourth Plan or early during the Fifth Plan period.

2. *Copper*: There is at present only one copper Smelter in the country which produces about 9,000 tonnes of metal per annum based on the Singhbhum (Bihar) Copper deposits. This unit, which is in the private sector, as been granted has licence under the Indus tries Act to set up a 16,500 tonnes per annum flash smelter for the production of copper. A 31,000 tonnes per annum copper smelter is being set up at Khetri (Rajasthan) in the public sector. These projects are expected to be completed by the end of the Fourth Plan. In addition, steps are being taken to develop the copper deposits in the Rakha area in Bihar, Agnigundala in Andhra Pradesh and Daribo in Rajasthan.

3. *Lead and Zinc*. The only lead smelter in the country at present is located at Tundoo (Bihar) with a capacity of about 5,400 tonnes per annum. Production in the smelter at present is, however, only of the order of 2,600 tonnes per annum. The smelter is based on the lead-zinc ore deposits of Zawar-Mines (Rajasthan).

A 20,000 tonnes per annum zinc smelter, based on imported concentrates, at Alwaye (Kerala) in the private sector went into production in May-June 1967. Another new zinc smelter with a capacity of 18,000 tonnes per annum based on Zawar (Rajas-

than) deposits in the public sector has recently been commissioned. Detailed proving and prospecting operations being initiated to determine the extent of additional ore reserves in this area have indicated that these reserves may ultimately sustain a metal production of over 75,000 tonnes per annum. A proposal received for expansion of the Alwaye (Kerala) smelter upto 60,000 tonnes per annum (in two stages) and another to set up a new 30,000 tonnes zinc smelter in the public sector, based on imported concentrates, are under active consideration.

With a view to locating and developing the potential mineral resources of the country in the sphere of non-ferrous metals, an integrated programme of air-borne survey and ground follow-up work has been drawn up. This programme envisages carrying out of air-borne surveys in the Aravalli area in Rajasthan, the East Cuddapah basin of Andhra Pradesh and Bihar Plateau covering an area of 120,000 sq. kms. Apart from the air-borne survey, the Geological Survey of India expect to take up ground surveys in respect of about 234 prospects.

EXPORT OF WAGONS TO U.S.S.R.

4324. SHRI MAHANT DIGVIJAI NATH: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the U.S.S.R. have asked for the supply of 10,000 eight-wheeler wagons; and

(b) if so, the estimated foreign exchange to be earned?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) Yes, Sir. Having regard to the technical and production problems, it is expected that, to begin with, 2000 Wagons will be exported in 1969-70. The figure of 10000 wagons per year is likely to be reached in 1972-73. An Indo-Soviet protocol, laying down a schedule of export of wagons, has been signed on 13-3-1968.

(b) It is too early now to make an estimate of foreign exchange to be earned. M18LSS(CP)68—4

STEEL AND WOODEN SLEEPERS LYING ALONG RAILWAY LINE

4325. SHRI BAL RAJ MADHOK: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that large quantities of steel and wooden sleepers have accumulated with the Indian Railways and that much of their stock is rotting along the railway lines in different areas;

(b) whether any estimate has been made of such stock; and

(c) if so, the steps which have been taken to exhaust that stock before ordering for new sleepers?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) No.

(b) and (c). Do not arise.

उत्तर रेलवे पर सब-ओवरसियर, मिस्त्री और ड्राफ्ट्समैन (नक्शानवीस)

4326. श्री निहाल सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के लगभग 205 सब-ओवरसियर, मिस्त्री प्रथम श्रेणी और नक्शानवीस दिसम्बर, 1967 से तकनीकी पक्ष से क्लर्की पक्ष में स्थानान्तरित कर दिये गये हैं और उनको उनकी पिछली सेवा तथा वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनके पहले पदों का वेतनमान 170 रुपये मासिक था और अब उनको 110 रुपये मासिक वेतन दिया जा रहा है और उनको दिसम्बर, 1967 तथा जनवरी, 1968 का उनका वेतन भी नहीं दिया गया है ;

(ग) उन कर्मचारियों को तकनीकी पक्ष से क्लर्की पक्ष में स्थानान्तरित किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या उन कर्मचारियों को उनके पहले पदों पर पुनः लगाने का सरकार का

विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री च०मु० पुनाचा) : (क) से (ग) कुछ निर्माण कार्यों के पूरा हो जाने के कारण उत्तर रेलवे में 95 सब-ओवरसियर मिस्त्री और 23 नक्शानवीस फालतू घोषित कर दिये गये हैं। सब-ओवरसियर मिस्त्री ग्रेड I और सहायक नक्शानवीस ग्रेड 'बी' के पदों का वेतन मान 150-240 रु० है। चूँकि तकनीकी ग्रेडों में समकक्ष पद नहीं थे इसलिए इन्हें गैर-तकनीकी पदों में समाहित किया गया। यह प्रश्न विचाराधीन है कि क्या नीचे के पदों में समाहित करने पर उन्हें ऊँचा वेतन दिया जा सकता है। इन कर्मचारियों की ओर से दिसम्बर 1967 और जनवरी, 1968 का वेतन न मिलने के सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं की गई है, लेकिन मामले की आगे जांच की जा रही है और जिन मामलों में कर्मचारियों को उनकी वकाया रकमें अदा नहीं की गई हैं, उनमें ज़रूरी कार्रवाई की जायेगी।

(घ) सरकार समस्या के इस पहलू पर विचार कर रही है।

बिहार में खानें

4327. श्री निहाल सिंह : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कितनी खानें हैं तथा उन में कौन-कौन से खनिज पदार्थ हैं ;

(ख) बिहार के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री कृष्णवल्लभ सहाय के पुत्र के नाम में कितनी और कौन-कौन सी खानें हैं तथा उन खानों से कौन-कौन से खनिज पदार्थ मिलते हैं; और

(ग) इन खानों से प्रतिवर्ष कितने खनिज पदार्थ मिलते हैं।

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (श्री च० खन्ना रेड्डी) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

चमड़ा निर्माण कम्पनियों

4328. श्री निहाल सिंह : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चमड़ा बनाने वाली कम्पनियों में काम करने वाले लोगों की संख्या कितनी है, इन कम्पनियों ने गत पांच वर्षों में कितने माल का निर्यात किया, यह सामान किन-किन देशों को निर्यात किया गया तथा उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई ;

(ख) ये कम्पनियां कितनी पूंजी से आरम्भ की गई थीं तथा इन कम्पनियों में इस समय कितनी पूंजी लगी हुई है; और

(ग) गत पांच वर्षों में उपर्युक्त प्रत्येक कम्पनी को कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गई?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) चमड़े का अधिकांश उत्पादन लघु तथा कुटीर उद्योग-क्षेत्र में होता है। समूचे चमड़ा उद्योग में काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या के बारे में ठीक-ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिर भी, संगठित औद्योगिक क्षेत्र में चमड़ा बनाने के एकक हैं और इन एककों में काम करने वाले लोगों की संख्या 13,500 है। गत 5 वर्षों में देश से निर्यात किए गए चमड़े की जानकारी विवरण में दी गई है जो सभा पटल पर रखा गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखियें संख्या LT-504/68]

(ख) चूँकि चमड़ा उद्योग गैर-सरकारी क्षेत्र में है और चमड़े का उत्पादन अधिकांश रूप में लघु तथा कुटीर उद्योगों में होता है, इसलिए विभिन्न एककों में विनियोजन का व्यौरा उपलब्ध नहीं है। संगठित क्षेत्र के

एककों की अचल आस्तियों में अनुमानित विनियोजन 10 करोड़ रुपये हैं।

(ग) संगठित क्षेत्र के विभिन्न एककों को गत पांच वर्षों में आवश्यक विदेशी मुद्रा निम्नलिखित थी :—

1962-63	203.96 लाख रुपये
1963-64	231.52 लाख रुपये
1964-65	191.44 लाख रुपये
1965-66	8.73 लाख रुपये
1966-67	45.33 लाख रुपये

—जून 1966 से कच्ची खालों, बहेड़े के सत, तथा छिलका आदि का आयात खुले सामान्य लाइसेंस से होता है।

(इनमें से कुछ एकक चमड़े के जूते तथा चमड़े के सामान भी बना रहे हैं।)

DURGAPUR STEEL PLANT

4329. SHRI BABURAO PATEL : Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to state:

(a) the cost likely to be incurred on the 7 man team of British experts arriving soon in India at his request to study Durgapur Steel Plant;

(b) why a team of foreign experts was considered necessary when Shri A. N. Banerji, Deputy Chairman of the Hindustan Steel, Ltd. said recently: "Durgapur Steel Plant is no longer a sick child. It is becoming healthier at a fast rate"; and

(c) whether there are no Indian experts to give advice and guidance on the working of the steel plants?

THE MINISTER OF STEEL, MINES AND METALS (DR. CHANNA REDDY):

(a) In regard to the British Steel Corporation team which visited Durgapur in February 1968, the expenditure on travel to India and back and the salaries of the experts were borne by the Government of U.K. under the Colombo Plan. The experts were treated as guests of Hindustan Steel Limited and the amount spent during

their stay in India was approximately Rs. 6,700/-.

(b) the Team was entrusted with the work of appraising the equipment and technical assistance requirements of Durgapur to be provided from the United Kingdom, which support is considered necessary in order to hasten the recovery of the Plant.

(c) Maximum advantage is being taken of available Indian expertise in placing the working of the Plant on an even keel. In view, however, of the fact that our resources of specialist personnel are fully stretched in the Context of organising production of expanded plants as well as the Alloy Steel Plant on an efficient basis, it is considered that selective support from the United Kingdom by way of equipment and technical assistance requirements, is indispensable to ensure rapid recovery at the Durgapur Steel Plant.

IMPORT POLICY

4330. SHRI HIMATSINGKA : SHRI RAMACHANDRA ULAKA :

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether the import policy has been recently revised so as to include some additional items in the permissible list of imported items;

(b) if so what are the major modifications in the previous import policy; and

(c) how far the imports are likely to increase during 1968-69 as a result of the revised policy?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) No major changes in the import policy announced for the period April, 1967-March, 1968 have been made in the recent past. Import policy for April, 1968-March, 1969 period is under review.

(b) Does not arise.

(c) It cannot be estimated at this stage.

QUOTAS OF STAINLESS STEEL

4331. SHRI HIMATSINGKA: Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to state:

(a) whether Government have received any complaints with regard to the misuse

of quotas of stainless steel in the different States and Union Territories;

(b) if so, the number of such complaints received during the last one year; and

(c) the action taken by Government to prevent such misuse and provide for further deterrent punishment for such misuse?

THE MINISTER OF STEEL, MINES AND METALS (DR. CHANNA REDDY):

(a) to (c). Information is being collected and will be placed on the Table of the House.

ENGINEERING UNITS IN WEST BENGAL

4332. SHRI HIMATSINGKA: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have received any proposal from the West Bengal Government to take over the management of the three engineering units in the States; and

(b) if so, the details thereof and the decision taken thereon?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

भिण्ड-चिरगांव रेलवे लाइन

4333. श्री रामावतार शर्मा :

श्री यशवन्त सिंह कुशावाह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिण्ड से चिरगांव तक बरास्ता लहर भंडरे रेलवे लाइन बिछाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस प्रयोजनार्थ सर्वेक्षण कब करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) जी नहीं ।

(ख) जिस लाइन के निर्माण का सुझाव दिया गया है, उसे अनाभाव के कारण चौथी योजना की अवधि में बनाने के विचारार्थ समुचित अप्रता मिलने की संभावना नहीं है । अगर इस लाइन को सुदूर भविष्य में बनाने पर विचार करना ही है तो इसके लिए अब शुरू किया जाने वाला सर्वेक्षण पुराना पड़ जायेगा और सर्वेक्षण का खर्च निष्फल हो जायेगा जिसे रेलों वर्तमान विषम अर्थोपाय स्थिति में शायद बर्दाश्त नहीं कर सकती ।

ENGINEERING UNIT IN WEST BENGAL

4334. SHRI INDRAJIT GUPTA: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large number of Engineering units in West Bengal are lying closed or locked-out for several months.

(b) if so, the reasons therefor and the details of the units concerned;

(c) whether Government had assured the State authorities of all possible assistance to get such units re-opened; and

(d) if so, the action taken in the matter?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

BOKARO STEEL PLANT

4335. SHRI INDRAJIT GUPTA:
SHRI BHOGENDRA JHA:

Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to state:

(a) whether disturbances have been taking place at the Bokaro Steel Plant over the question of employment; and

(b) if so, the policy followed by the management regarding absorption of local people whose lands have been acquired for the project?

THE MINISTER OF STEEL, MINES AND METALS (DR. CHANNA REDDY):

(a) No, Sir. Only a demonstration was staged on 8th February, 1968. In a subsequent meeting with the Mukhyas and other representatives of the local people, policy adopted by Bokaro Steel Ltd. in the matter of employment and trade facilities was explained to their entire satisfaction. The agitation has now completely died down.

(b) According to the policy laid down by Government, first preference is being given to the displaced persons in the matter of employment in BSL in unskilled and semi-skilled jobs. With a view to improve their prospects of employment, a special scheme for training of displaced persons has also been introduced and as on 31st January, 1968, 307 displaced persons were under-going training under this scheme. The displaced persons were also receiving preference in allotment of shops. They are also receiving preference in other trades and in award of small contracts. Besides, in the matter of rehabilitation, Bokaro Steel Ltd. is contributing 50% of the cost of rehabilitation which is estimated at Rs. 4.2 millions.

DURGAPUR STEEL PLANT

4336. SHRI INDRAJIT GUPTA: Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to state:

(a) whether the team of experts from U.K. has completed its study of the Durgapur Steel Plant;

(b) the problems entrusted to the team;

(c) whether the team's report has been received; and

(d) if so, Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STEEL, MINES AND METALS (DR. CHANNA REDDY):

(a) Yes, Sir.

(b) The team was entrusted with the work of appraising the requirements of Durgapur Steel Plant for fully effective operation and to indicate the equipment and technical assistance that would be appropriate to provide from Britain in the light of the organisational, managerial, administrative and other conditions including industrial relations that would obtain at the steel-works.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

MESSRS. GUZDAR KAJORA COAL MINES LTD., AND MESSRS CALCUTTA SAFE DEPOSIT CO. LIMITED

4337. SHRI INDRAJIT GUPTA: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that M/s. Guzdar Kajora Coal Mines Limited and M/s. Calcutta Safe Deposit Company Limited have not been holding their Annual General Meetings nor issuing any Annual Reports and Balance Sheets, for the last several years;

(b) whether these firms have also violated other provisions of the Companies Act; and

(c) if so, action taken against them?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED):

(a) to (c).

A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See No. LT-505/68.*]

कपास के मूल्य

4338. श्री रघुबीर सिंह शास्त्री : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देसी कपास तथा नई कपास पर नियंत्रण लगाने तथा ऋण देने पर प्रतिबन्ध लगाने की नीति के विरुद्ध काटन फंडरेशन, सेंट्रल जोन, अमरावती से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शाफी कुरेशी) : (क) तथा (ख). फंडरेशन ने हाल ही में दो ज्ञापन भेजे हैं। इन में से एक भारतीय सूती कपड़ा मिल्स संघ को दिया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह अनुरोध किया गया है कि संघ अपने सदस्यों द्वारा कपास खरीदने पर प्रतिबन्ध लगाने के निर्णय पर तथा कपास के लिए ऋण की छूट पर अपनी आपत्तियां वापिस लेने के निर्णय पर पुनः विचार करे। सरकार ने विद्यमान मौसम के लिए

निर्धारित कपास के भण्डार स्तरों में कमी नहीं की। फिर भी इण्डियन काटन मिल्स फ़ैड-रेज्जान के सदस्य आत्म-अनुशासन के उपाय के तौर पर इन स्तरों तक कपास नहीं खरीद रहे हैं। बैंक ऋण का स्तर सभी सम्बद्ध व्यक्तियों के हितों की दृष्टि में रखते हुए निश्चित किया जाता है। कपास के मूल्य अभी तक पिछले वर्ष के अधिकतम निर्धारित मूल्यों से काफी ऊपर चल रहे हैं। फिर भी सरकार स्थिति पर सदा ध्यान रखती है तथा उपयुक्त समय पर यथा-वश्यक कदम उठाने पर विचार किया जायेगा।

CLOSURE OF NEW VICTORIA MILLS

4339. SHRI BHOGENDRA JHA : Will the Minister of COMMERCE be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 153 on the 13th February, 1968 and state :

(a) whether any decision has since been taken on the recommendation of the Committee set up under the Industries (Development and Regulation) Act;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether any action has been or is being taken against the Individuals responsible for the closure of the Mills ; and

(d) whether Government propose to include workers' representatives in the Management to run the mill more efficiently ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : (a) No, Sir.

b) Does not arise.

(c) No, Sir. Closure of this mill has not attracted the panel provisions of law.

(d) Till the mill is not taken over by Government, the question of including worker's representatives in the management does not arise.

ASHOKA PAPER MILLS LTD.

4340. SHRI BHOGENDRA JHA : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1295 on the 20th February 1968 and state :

(a) whether Government are aware that the present Government of Bihar have de-

ecided to reverse the decision of the previous Government to take over the Ashoka Paper Mills Ltd.;

(b) whether it has been decided to allow the mill to go into liquidation;

(c) whether Government are aware that it has been done by the present Government of Bihar to oblige the Birlas who want to grab this mill at no cost; and

(d) whether Government propose to take over the Mills ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (a) Yes, Sir. According to the information received in this Ministry on 22-2-68 from the Government of Bihar it transpires that they have changed their earlier decision in the matter.

Attention in this connection is invited to the Statement laid on the Table of the House today correcting the answer given to the Unstarred Question No. 1295 on 20-2-68 referred to by the Member.

(b) the Company was floated in the private sector and Government have no information whether or not the Management has decided to send it into liquidation.

(c) We have no information.

(d) No, Sir.

CLOSURE OF COAL MINES

4341. SHRI BHOGENDRA JHA : Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1291 on the 20th February, 1968 and state :

(a) whether it is a fact that several mines of the National Coal Development Corporation in Giridih have been or are likely to be closed down as the coal produced therein has not been sold out;

(b) whether it is also a fact that the private collieries charge higher prices from the public undertakings; and

(c) if so, the reasons for not giving priority to N.C.D.C. coal ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL, MINES AND METALS (SHRI P. C. SETHI) : (a) No, Sir.

(b) Some private collieries despatching coking/blendable coals to two public undertakings are charging prices higher than that being charged to Washeries/Steel Plants. So far as non-coking coal supply is concerned, no such fact has come to the knowledge of Government.

(c) The National Coal Development Corporation is at present fully booked in their supply of high grade coking coal. There is no proposal under consideration to give priority to NCDC coal.

FREE TRADE ZONE AT KANDLA

4342. SHRI R. K. AMIN ;
SHRI P. N. SOLANKI ;
SHRI D. R. PARMAR :

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the development of Free Trade Zone at Kandla has been delayed ;

(b) if so, the reasons there for; and

(c) the action Government propose to take to expedite the work ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : (a) No, Sir. The major items of development works in the Kandla Free Trade Zone have been completed and facilities such as developed plots, roads, water electricity and power etc. necessary for setting up of industries have been made available.

(b) and (c). Do not arise.

MISUSE OF CONCESSION TICKETS

4343. SHRI R. K. AMIN ;
SHRI P. N. SOLANKI ;
SHRI D. R. PARMAR :

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is fact that the concession tickets issued for a party of five or more persons for travelling more than 1500 kilometres can be used for more than one party;

(b) whether the Railway Administration has detected such cases of misuse of this facility; and

(c) if so, further action taken by Government to prevent such misuse ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA) : (a) The hon'ble Members presumably have in view the circular tour tickets. They are issued subject to the circular tour covering a distance of 2,400 kms. or more but no minimum number of passengers is laid down. They are, in fact, intended to be issued to individuals.

Such tickets are not transferable.

(b) Shri R. K. Amin recently brought it to my notice that such tickets were being misused.

(c) The question of tightening the checks and making the conditions more stringent is being examined.

S. PPLY OF COPPPER BARS BY THE STATE TRADING CORPORATION

4344. SHRI R. K. AMIN
SHRI D. N. SOLANKI
SHRI D. R. PARMAR

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that small manufacturers of vessels find it difficult to obtain copper bars from the State Trading Corporation ;

(b) whether it is also a fact that the price charged by the State Trading Corporation for them is much higher than the price prevailing in the market; and

(c) if so, the action taken in the matter ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : (a) State Trading Corporation does not import or supply Copper Bars. This is done by the Minerals and Metals Trading Corporation of India Ltd. The M.M.T.C. sells copper imported by them against release orders issued by the Licensing authorities. Since the middle of February 1968 the Corporation does not have any stock with them. Prior to that if small manufacturers of vessels were allocated copper by the authorities concerned, M.M.T.C. did offer this material to the small producers.

(b) Copper is allowed to be imported only by the actual users or the M.M.T.C. Legally therefore, there is no free market for

this metal. The market prices ranged between Rs. 11,500/- to 12,500/- per M/ton from May 1967 to February, 1968. From end of February, 1968 market quotations have ranged between Rs. 12,600 to Rs. 13,000/- per metric ton. M.M.T.C.'s selling price has been Rs. 12,100/- per metric ton for electrolytic copper ingot bars and Rs. 11,500/- per metric ton for Fire Refine Copper.

(c) In view of (b) above does not arise.

BARTER TRADE AGREEMENTS

4345. DR. KARNI SINGH : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) the names of countries with which India have barter trade agreements;

(b) the goods exported from India against such agreements—how much agriculture based and how much industrial;

(c) whether efforts have been made to enter in to similar agreements with other countries to whom India is at present required to pay in foreign exchange for item of import; and

(d) if so, the details thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : (a) There is no barter deals on Government-to-Government basis between India and other countries. S.T.C. and M.M.T.C. have entered into barter deals. They are with U.S.A., West Germany, France and Sweden.

(b) A statement is laid on the Table of the House [Placed in Library. See No. LT-506/68].

(c) Yes, Sir.

(d) Action is in progress to explore possibilities of barter deals with West Germany, France, Greece, Norway, Finland, Japan and the U.S.A. As efforts are still continuing no details can be given on this stage.

TALKS WITH SOVIET PRIME MINISTER

4346. DR. KARNI SINGH : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) the details of the talks held by him with Mr. Kosygin during the latter's recent visit to India;

(b) whether any suggestions were made to set up fresh joint ventures by India and the Soviet Union;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the reaction of Mr. Kosygin to such suggestions and the fields in which he found such joint ventures feasible ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : (a) to (d). The discussions with Mr. Kosygin, the Soviet Premier included the subject of joint Industrial Collaboration between India and USSR in the fields of Jute goods, footwear and other leather goods, readymade garments and fruit juices. He was agreeable with this idea in principle. There was an assurance from Premier Kosygin that USSR is prepared to purchase all the railway wagons India can spare for supply to USSR. USSR also agreed to buy steel rails. As a result of these discussions, the Soviet Premier agreed to send experts in various fields to discuss and finalise the plans.

रायपुर में विद्यार्थियों द्वारा रेलगाड़ी का रोक जाना ।

4347. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 जनवरी, 1968 को "नवभारत टाइम्स" में प्रकाशित हुए इस समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि रायपुर में एक रेलगाड़ी को छात्रों ने रोक लिया था;

(ख) यदि हां, तो यह रेलगाड़ी किस कारण रोक ली गई थी और इसके परिणाम-स्वरूप यह रेलगाड़ी कितनी लेट हो गई थी; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाएं न होने देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री जे० मु० पुनाचा) :

(क) 14 जनवरी, 1968 के "नवभारत टाइम्स" में ऐसा कोई समाचार नहीं छपा है। लेकिन 10-1-68 के "नवभारत"

में जो रायपुर से प्रकाशित होता है, 9-1-68 को रायपुर में निकट विरधी कालोनी में एक गाड़ी के रोके जाने का जिक्र था।

(ख) 9-1-68 को कुछ विद्यार्थियों द्वारा खतरे की जंजीर खींचे जाने के कारण रायपुर से 2.7 किलोमीटर दूर विरधी कालोनी के समीप किलोमीटर 851/7 पर 353 अप हावड़ा-डोंगरगढ़ सवारी गाड़ी को 7 मिनट क लिए रोका गया था। विद्यार्थियों की इस कार्यवाही का कारण ज्ञात नहीं है।

(ग) अनधिकृत रूप से खतरे की जंजीर खींचने के ऐसे मामलों की रिपोर्ट आवश्यक कार्यवाही के लिए राज्य सरकार और पुलिस प्राधिकारियों को की जाती है।

रूस को इंजीनियरी माल का निर्यात

4 श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966 और 1967 में भारत द्वारा रूस को कितने मूल्य के इंजीनियरी माल का निर्यात किया गया;

(ख) उससे कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई; और

(ग) 1968-69 के अन्त तक कितने मूल्य के इंजीनियरी माल का निर्यात किये जाने की सम्भावना है और उससे अनुमानत : कि विदेशी मुद्रा कमाई जायेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरंशी) : (क) तथा (ख). वर्ष 1966 में भारत द्वारा रूस को 32.1 लाख ६० मूल्य के इंजीनियरी माल का निर्यात किया गया। जनवरी से नवम्बर, 1967 में 2.912 करोड़ ६० के मूल्य का निर्यात हुआ, जिसमें बीम तथा नाली भी शामिल हैं।

(ग) पंचांग वर्ष 1968 में सोवियत रूस को 13 करोड़ ६० मूल्य के बेल्लित इस्पात के उत्पादों (बीम, नाली तथा कोण) का निर्यात किया जायेगा, इसके अलावा 1.4

करोड़ ६० मूल्य के अन्य इंजीनियरी माल जैसे संचायक, मोटरगाड़ी का सहायक सामान, छोटी खराद के उपकरण, छोटे लैम्प आदि का निर्यात भी किया जायेगा।

जूतों का निर्यात

4349. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस और अमरीका में भारत में बने जूतों की मांग बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो 1967-68 के अन्त तक कितने मूल्य के जूतों का निर्यात किये जाने की सम्भावना है और उससे कितनी विदेशी मुद्रा की कमाई होगी; और

(ग) 1966 और 1967 में रूस और अमरीका को कितने मूल्य के भारत में बने जूतों का निर्यात किया गया तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरंशी) : (क) जी, हां।

(ख) 1967-68 के अन्त तक रूस और अमरीका को क्रमशः लगभग 3.50 करोड़ ६० तथा 50 लाख ६० के मूल्य के जूतों के निर्यात का अनुमान है।

(ग)

	मूल्य लाख रुपये में	
	1966	1967
		जनवरी- नवम्बर)
रूस	475	306
अमरीका	62.96	104.71

मध्य प्रदेश में कोयले तथा लोहे की खानें

4350. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के सरगुजा, सिद्धी और पन्ना जिले में कोयले और लोहे की कितनी खानें हैं;

(ख) इन कोयला खानों से प्रति वर्ष कितना लोहा और कोयला निकलता है;

(ग) इन कोयला खानों में कितने कर्मचारी और श्रमिक काम कर रहे हैं;

(घ) उनमें काम करने वाले श्रमिकों को कितनी अवधि के पश्चात् स्थायी किया जाता है; और

(ङ) 1965 से 1967 तक की अवधि के दौरान कितने श्रमिकों को स्थायी बनाया गया था ?

इस्यार्त, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बिहार का औद्योगिक विकास

4351. श्री रामावतार शास्त्री : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले बिहार के औद्योगिक विकास की स्थिति क्या थी और इस समय क्या है ;

(ख) उस राज्य में स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले बड़े तथा छोटे उद्योगों की पृथक्-पृथक् संख्या क्या थी और इस समय क्या है ; और

(ग) देश में औद्योगिक विकास के क्षेत्र में बिहार की स्थिति क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है । और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम का स्टाक

4352. श्री चन्द्रिका प्रसाद : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनिज तथा धातु व्यापार निगम के पास इस समय जो वस्तुएं हैं उनका ब्योरा क्या है, प्रत्येक वस्तु का प्रति क्विंटल मूल्य कितना है तथा वे वस्तुएं उनके गोदामों में कब से पड़ी हुई हैं ; और

(ख) राज्यों और व्यापारियों को उस निगम के माध्यम से विभिन्न वस्तुओं का वितरण करने के नियम क्या हैं तथा सरकार के पास उन वस्तुओं का कितना स्टाक है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरंशी) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या LT/507/168]

(ख) खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा आयातित कच्चा माल अथवा सम्बद्ध प्रायोजक अधिकारियों की सिफारिश के अनुसार राज्य लघु उद्योग निगम के माध्यम से अथवा वास्तविक उपयोक्ताओं में सीधे वितरित किया जाता है । इस कच्चे माल का सरकार स्टाक नहीं रखती ।

लघु उद्योगों के लिये आयात लाइसेंस

4353. श्री चन्द्रिका प्रसाद : क्या वाणिज्य मंत्री 8 दिसम्बर, 1967 के अतरांकित प्रश्न संख्या 3615 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग निदेशक कानपुर द्वारा 1573 आवेदकों के लिये सिफारिश किये गये आयात लाइसेंसों का कुल मूल्य कितना है और वास्तव में जारी किये गये आयात लाइसेंसों का मूल्य कितना है ;

(ख) इन आवेदकों को लाइसेंस देने के माप दण्ड क्या हैं ।

(ग) क्या कुछ आवेदकों के आयात लाइसेंस के आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिये गये हैं और यदि हां, तो प्रत्येक मामले में किन कारणों से ऐसा किया गया है ; और

(घ) क्या इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपसत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और बाद में दे दी जायेगी ।

MANUFACTURE OF POWER TILLERS

4354. SHRI DEORAO PATIL : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) the names of the schemes which have been licensed/approved under the Industries Act for the manufacture of Power tillers/small tractors, below 12 DBHP during the year 1967-68;

(b) the names of schemes which are under consideration at present; and

(c) when the decision on the pending schemes is likely to be taken ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (a) M/s. J. K. Cotton Spinning & Weaving Mills Ltd., Kanpur were granted an industrial licence on 29-4-67 for the manufacture of LB-17 Hand Tractors for a capacity of 6,000 Nos. per annum.

(b) The schemes submitted by the following parties are under consideration :

(1) Punjab State Industrial Development Corporation Ltd., Chandigarh for the manufacture of 4-wheeled Power tillers in an industrial undertaking to be set up at Ludhiana.

(2) M/s. F. W. Heilgers P. Ltd. New Delhi for the manufacture of Kubota Power tillers in a new industrial undertaking to be set in the State of Orissa.

(3) M/s. Indequip Engineering Co. Ltd. Ahmedabad for the manufacture of Robin Power tillers in their existing industrial undertaking at Ahmedabad in the State of Gujarat.

(c) Final decision on these schemes is likely to be taken shortly.

रुई का आयात

4355. श्री देवराव पाटिल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश को रुई की कितनी आवश्यकता है और कितनी रुई के लिये विदेशों को क्रयादेश दिये गये हैं ;

(ख) पी० एल० 480 निधियों के अन्तर्गत वर्ष 1967-68 में और जनवरी तथा फरवरी 1968 में कितनी रुई का आयात किया गया ;

(ग) क्या यह सच है कि रुई का आयात ऐसे समय पर किया जाता है जब देशी रुई के विपणन का मौसम होता है जिसके परिणाम स्वरूप देशी रुई के मूल्य गिर जाते हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार रुई के आयात के बारे में अपनी नीति में परिवर्तन करने का है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) अनुमान है कि पूर्वाविशष्ट भण्डार की सामान्य मात्रा को छोड़कर, 1967-68 के वर्ष में देश में 68 लाख रुई की गांठों की आवश्यकता होगी जिसमें से 64 लाख गांठों की खपत मिलों में हो जायेगी। इस वर्ष 9.76 लाख गांठें आयात करने का कार्यक्रम है। यह बताना सम्भव नहीं है कि मिलों ने कितनी मात्रा के लिये आर्डर दिये ।

(ख) जैसा कि व्यापार स्रोतों से पता चला है, पी एल० 480 के अन्तर्गत सितम्बर 1967 से 17 फरवरी 1968 तक अनुमानतः 167,598 गांठों का आयात किया गया

है जिसमें से जनवरी तथा फरवरी, (17 तारीख तक) में क्रमशः 23, 202 तथा 51,489 गठों पहुंची हैं।

(ग) तथा (घ) जी, नहीं। उद्योग की आवश्यकता को पूरा करने के लिये देशी रुई की कमी को पूरा करने की आवश्यक सीमा तक ही रुई के आयात की व्यवस्था की जाती है। आयात का समय अन्य बातों के साथ साथ उन देशों में रुई चुनने तथा विपणन के मौसमों पर भी निर्भर करता है जहां-जहां से रुई का आयात किया जाता है।

FERRO-MANGANESE INDUSTRY

4356. DR. RANEN SEN : Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to state:

(a) whether the ferro-manganese industry is in a crisis due to large accumulation of unsold stocks with it;

(b) whether it is a fact that the Hindustan Steel, Ltd. had failed to lift the indented 62,000 tonnes of ferro-manganese during the current year;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) the steps which have been taken to help the industry to tide over the present crisis ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL, MINES AND METALS (SHRI P. C. SETHI) : (a) There has been accumulation of stocks with the Ferro-Manganese producers.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) It is expected that with improvement in the general economic situation, internal off take will progressively increase. Efforts are also being made to step up exports of Ferro-Manganese to the extent possible.

USE OF FUEL AND STEAM IN INDUSTRIES

4357. DR. RANEN SEN : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Dr. Tanaka, Asian Productivity Organisation's expert in fuel efficiency

had recently visited India to study combustion of fuel and steam in a number of Indian industries;

(b) if so, the findings of his study ;

(c) whether he has made any suggestions regarding the use of fuel and steam in Indian industries; and

(d) if so, the main suggestions made by him and Government's reaction thereto ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (a) to (d) Dr. Kusuyata Tanaka, Chief, Combustion Division, Resources Research Institute, Agency of Industrial Science and Technology, Japan, visited India recently on an invitation from the National Productivity Council (NPC) India, through the Asian Productivity Organisation (APO), Tokyo. Dr. Tanaka will first submit his report to APO which, in turn, will transmit it NPC after getting it translated into English. The report is still awaited by NPC. Dr. Tanaka also made some "on-the-spot" suggestions to the industries and factories he visited about better utilisation of fuel and steam, which they have treated as confidential. Before his departure from India on the 22nd February, 1968 a press Conference was held on the 21st February 1968 in which Dr. Tanaka highlighted the following points in his talk with the pressmen :—

- (1) The first step to utilise fuel more effectively could be to educate on a wide scale engineers and operators in charge of fuel consuming plant in the proper techniques of burning fuel and also carry on a massive propoganda in this matter. Dr. Tanaka expressed the hope that NPC Fuel Efficiency Service would play a significant role in this direction.
- (2) India should evolve suitable designs of boiler and furnaces of high efficiency based on indigenously available fuel to replace old and antiquated fuel-consuming plants like Lancashire boilers and old furnace designs.
- (3) India should, as far as possible, attempt to utilise low grade coals extensively and the Government should provide incentives to the fuel

users to change over to low grade coal by increasing price differential between high grade coal and low grade coal.

- (4) Suppliers of coal should maintain certain standard of coal so as to help the consumer in utilising them effectively.
- (5) The Indian Industry should have some simple instruments like analyser and drought gauges to keep a check on combustion efficiency.
- (6) Change over to fuel oil may not be in the ultimate advantage of the country since the entire demand of fuel oil could not be met indigenously and as India was forced to import substantial amount of fuel oil from abroad involving precious foreign exchange, he felt that till such time when India had a favourable balance of trade with the foreign countries, the use of fuel may be restricted to certain specialised applications.
- (7) Dr. Tanaka' also emphasised the need to evolve proper standards to enforce strict control in practice over sampling and analysis of coal.

The National Productivity Council Fuel Efficiency Engineers are drawing the attention of the industry to these points.

METAL CORROSION

4358. SHRI DHIRESHWAR KALITA : Will the Minister of STEEL MINES AND METALS be pleased to state :

(a) whether experts have calculated that India was losing over Rs. 150 crores annually as a result of metal corrosion; and

(b) if so, the steps which have been taken to combat metal corrosion ?

THE MINISTER OF STEEL, MINES AND METALS (DR. CHANNA REDDY)

(a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर जिला मुख्यालय का बदला जाना

4359. श्री क० मि० मधुकर : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर जिले के मुख्यालय को मुजफ्फरपुर बदलने का निर्णय किया गया था और इस उद्देश्य से भूमि भी अर्जित कर ली गई थी; और

(ख) यदि हां, तो मुख्यालय को मुजफ्फरपुर न बदले जाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री च० म० पुनाचा) : (क) रेल मंत्रालय द्वारा इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं किया गया था।

(ख) सवाल नहीं उठता।

हाजीपुर और भँसालोटन के बीच रेलवे लाइन

4360. श्री क० मि० मधुकर : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह निर्णय किया गया है कि पूर्वोत्तर रेलवे में हाजीपुर और भँसालोटन जो गंडक नहर का उद्गम स्थल है, के बीच साहबगंज तथा गोविन्दगंज से होती हुई रेलवे लाइन बिछाना लाभप्रद रहेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस लाइन को बिछाने का काम कब आरम्भ किया जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री च० म० पुनाचा) :

(क) और (ख). अतीत में इस प्रकार के प्रस्ताव के लिए कोई सबक्षेप नहीं किया गया है। हाजीपुर और बगहा पहले से ही एक मीटर आमान लाइन से, जो मुजफ्फरपुर, सगौली और नरकटियागंज होकर जाती है, जुड़े हुए हैं। फिर भी यह उल्लेखनीय है कि 1962 में पूर्वोत्तर रेलवे ने बगहा और भँसालोटन के बीच इंजीनियरिंग और यातायात सम्बन्धी प्रारम्भिक सर्वेक्षण बिहार सरकार के खर्च पर किया था जिसने मुख्यतः गंडक प्रायोजना करने के लिए सामान भेजने की सुविधा की दृष्टि से यह प्रस्ताव रखा था। तब यह प्रस्ताव काफी अलाभप्रद समझा गया था। जब राज्य सरकार को सर्वेक्षण का परिणाम बताया गया

तो उसने सूचित किया कि वह अब इस रेल सम्पर्क के निर्माण में रुचि नहीं रखती । इसलिए बगहा और भंसालोटन के बीच रेल सम्पर्क निर्माण के लिए अब कोई औचित्य नहीं है ।

TRADE WITH IRAQ

4361. SHRI R. BARUA : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether the exports of Indian goods to Iraq have shown any improvement ;

(b) whether the prospects of developing and diversifying trade between India and Iran have also been explored ;

(c) whether trade expansion with these countries is also to be linked up with the establishment of joint ventures in the field of industries ; and

(d) if so, the details thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : (a) and (b) Yes, Sir.

(c) and (d). Trade expansion with these countries is not specifically linked with the establishment of joint ventures but joint ventures do help in the expansion of trade through export of capital goods and machinery. All possible encouragement is given by Government to the Indian Industrialists, desiring to set up joint ventures in these countries.

सूती कपड़ा फैक्टरी जावरा में आग लगने की दुर्घटना

4362. श्री निहाल सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में जावरा में एक सूती कपड़ा फैक्टरी में आग लग जाने के कारण 28 लाख रुपये की हई जल गई थी ;

(ख) यदि हां, तो आग लगने का क्या कारण था ;

(ग) क्या यह सच है कि इस फैक्टरी का बीमा हुआ था, और अभी तक बीमा की राशि नहीं दी गई है ;

(घ) यह फैक्टरी केन्द्रीय सरकार क्षेत्र में या राज्य सरकार के क्षेत्र में है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने फैक्टरी के लिये कितनी सहायता मंजूर करना स्वीकार किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभापटल पर रख दी जायेगी ।

TRANSFER OF RAILWAY OFFICERS

4363. SHRI B. K. DASCHOWDHURY : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the policy regarding the transfer of Railway Officers from one place to another ; and

(b) the length of stay of officers in Calcutta and Delhi area ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA) : (a) Transfers are made only when administratively considered necessary. There is no rigid limit but officers holding key posts are not normally retained at one place for unduly long periods.

(b) The information is being collected and will be placed on the table of the Sabha.

इस्पात कारखाने

4364. श्री मधु लिये : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र में तीन इस्पात कारखानों के विस्तार कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस में अब तक कितनी धनराशि लग चुकी है ;

(ग) क्या भद्रावती कारखाने का भी विस्तार किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इन कारखानों के विस्तार कार्यक्रम की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख) . चीनी पंच वर्षीय योजना की रूपरेखा के मसौदे में सरकारी क्षेत्र के तीन इस्पात कारखानों के विस्तार कार्य के लिए निम्नलिखित धनराशि रखी गई है :

कारखाने का नाम	इस्पात पिण्ड की क्षमता (मिलियन टनों में)	कुल खर्च (करोड़ रुपये)
भिलाई इस्पात कार-खाना	2.5 से 3.2	62.90
*छठी धमन भट्ठी समूह	*	23.00
दुर्गापुर इस्पात कार-खाना	1.6 से 3.4	312.20
राउरकेला इस्पात कारखाना	1.8 से 2.5	100.00

2. इस्पात की मांग कम होने तथा साधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात कारखानों का विस्तार कार्य स्थगित कर दिया गया है । भिलाई इस्पात कारखाने के विस्तार के लिए विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन अभी तैयार किया जाना है । इस बीच इसके विस्तार के प्रथम-चरण का काम, जिसमें कोक और लोहा बनाने की सुविधायें होंगी, हाथ में लिया गया है । इस काम पर कुल 254.52 मिलियन रुपये खर्च आने का अनुमान है । इसमें से 31 मार्च, 1967 तक 45.7 मिलियन रुपये खर्च हो चुके थे ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(*) भिलाई इस्पात कारखाने का 2.5 मिलियन टन के बाद का विस्तार दो चरणों में किया जाएगा—प्रथम चरण में छठी धमन भट्ठी समूह स्थापित किया जाएगा ।

चाय पर निर्यात शुल्क

4365. श्री मधु लिमये : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चाय पर लगे निर्यात शुल्क में कमी कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कमी के फलस्वरूप भारतीय चाय अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता कर सकेगी ; और

(ग) इस समय अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका और भारत की एक जैसी किस्मों की चाय का मूल्य क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, हां ?

(ख) श्रीमान्, गेमी आशा है ।

(ग) चाय की किस्म निर्धारित करने के लिए किसी मानक वर्गीकरण के अभाव में एक देश द्वारा बाजार में भेजी गई चाय की प्रत्येक किस्म की अन्य देशों द्वारा पैदा की गई तथा बाजार में भेजी गई चाय से तुलना करना सम्भव नहीं है ।

चीनी संयंत्रों और मशीनों का निर्माण

4366. श्री मधु लिमये : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चीनी संयन्त्र और मशीनें बनाने की वर्तमान क्षमता कितनी है ;

(ख) क्या चीनी बनाने वाली मशीनें निर्यात करने की कोई योजना बनाई गई है ।

(ग) ऐसी मशीनों के किन देशों में बिकने की सम्भावना है ;

(घ) क्या आगामी तीन वर्षों में ऐसी मशीनों के निर्यात और उत्पादन के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है ; और

(इ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं।

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) यह उद्योग 15 करोड़ रु० के मूल्य की प्रति वर्ष चीनी मिल मशीनें बना सकता है।

(ख) और (ग) : सम्पूर्ण चीनी मिल संयंत्रों पुर्जों और फालतू पुर्जों के निर्यात की सम्भावना का लगातार पता लगाया जा रहा है। भारत में निमित्त चीनी मिल मशीनों में युगांडा, फिलीपाइन, घाना, लंका, नाइजीरिया, जर्मनी के संघीय गणराज्य, बर्मा, इण्डोनेशिया तथा जर्मनी के लोकतन्त्रात्मक गणराज्य द्वारा रुचि दिखाई जाने का संकेत मिला है।

(घ) और (ङ) ऐसे कोई लक्ष्य निश्चित नहीं किए गए हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना में इस वर्ष के अन्त तक बनकर तैयार हो जायगी, नई योजना की अवधि में इस बारे में लक्ष्य बताये जा सकते हैं।

ROLL GRINDING MACHINES

4367. **SHRI CHANDRA SEKHAR SINGH :** Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Heavy Engineering Corporation has entered into an agreement for technical collaboration with a West German firm for the manufacture of roll grinding machines; and

(b) if so, the terms of the agreement ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (a) yes Sir.

(b)(i) the foreign company will be paid a lump-sum amount of DM 11.25 lakhs equivalent to Rs. 21.22 lakhs at the current rate exchange payable as follows:—

(a) 20% payable within 30 days of signing of the agreement;

(b) 20% payable on delivery of the complete design and technological documents against despatch documents;

(c) balance of 60% payable in six equal half yearly instalments, the first instalment being paid after six months from the date of despatch of the last consignment of the design and technological documents.

(ii) exports of the manufactured products will be freely permitted;

(iii) the period of the agreement will be eight years from the date of signing of the agreement. Further extension will be only with the prior approval of the Government of India.

PAPER INDUSTRY

4368. **SHRI S. S. KOTHARI :** Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the profitability of paper industry has been declining for the last few years and a number of units have recently been incurring losses; and

(b) if so, the steps taken by Government to assure reasonable profitability to the paper industry so that expansion of the industry is not hampered ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT & COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (a) It has been reported by the Paper Industry and also by the Development Council for Paper, Pulp and Allied Industries that the profitability of the industry has been declining for the past few years and some of the mills have closed down.

(b) The matter is under consideration by Government.

MANUFACTURE OF SCOOTERS

4369. **SHRI S. S. KOTHARI :** Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that inspite of the notification issued in March, 1965 for the expansion of capacity for manufacture of

150 c.c. scooters, Government has not so far taken any decision in the matter;

(b) if so, the reasons for the delay;

(c) whether it is a fact that the technical sub-Committee set up in September, 1967, to screen the select list of scooters applicants for expansion of capacity has not so far finalised its recommendations; and

(d) if so, by what time Government propose to clear licensing and other formalities to enable new entrepreneurs to commence construction of factories?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT & COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) Yes.

(b) to (d): The screening of the large number of applications received as the result of the notification issued in March, 1965 had to be kept pending for a time awaiting fixation of the 4th Plan target for scooters and ascertainment of the extent to which the existing units could be expected to contribute towards that target. Besides these have had to be considered on *inter se* merits of each case. The sub-committee of the licensing committee set up to examine the pending schemes has concluded its deliberations and its report will be submitted in the next few days. Government expect to be in a position to take a final decision after the report of the sub-committee has been received and considered by the licensing committee and the latter has made its recommendations.

RAILWAY MONTHLY SEASON TICKETS

4370. SHRI YASHPAL SINGH: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state.

(a) whether it is a fact that the rate of Season ticket from New Delhi to Meerut which is 60 miles from Delhi is Rs. 21 p. m. whereas from Delhi to Sonapat which is 29 miles from Delhi, it is Rs. 18 p. m. and

(b) if so, the reasons therefor and the action taken to remove this disparity?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) The Third Class Monthly Season Ticket fare from Delhi to Meerut City, a distance of 68 kms. is Rs. 22.80 and from Delhi to Sonapat

a distance of 44 kms., Rs. 15.60.

(b) In view of the reply to part (a), the question does not arise.

MANUFACTURE OF PRINTING MACHINES

4371. SHRI SHIVA CHANDRA JHA :
SHRI SATYA NARAIN SINGH:
SHRI E. K. NAYANAR :
SHRIMATI SUSEELA GOPALAN:
SHRI C. K. CHAKRAPANI :

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some agreement has been reached between the Hindustan Machine Tools and M/s. Albert Frankenthal of West Germany for the setting up of a factory for the manufacture of printing machines in India; and

(b) if so, the main features thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT & COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) and (b). Hindustan Machine Tools Ltd., have a proposal for the establishment of a subsidiary company in collaboration with Messrs. Albert Frankenthal of West Germany for the manufacture of some items of printing machinery. The terms of the agreement are yet to be finalised.

EXPORT OF RADIO SETS TO U.S.A.

4372. SHRI SHIVA CHANDRA JHA : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that India exports radio sets to U. S. A. and other countries:

(b) if so, how many have been exported in 1967, and to which countries and the amount of foreign exchange earned therefrom; and

(c) if not, how many are imported, if any to India per year and from which countries and how much foreign exchange is spent thereon annually?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House. *Placed in Library. See No. LT—1312/68*

(c) Import of Radio Sets in India is banned.

ROURKELA STEEL PLANT

4373. SHRI YASHPAL SINGH : Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to state:

(a) whether Government have decided to set up some more units in Rourkela Steel Plant;

(b) if so, when these units will be installed there; and

(c) the amount likely to be involved therein ?

THE MINISTER OF STEEL, MINES AND METALS (DR. CHANNA REDDY):

(a) to (c). The Rourkela Steel Plant is presently being expanded from 1.0 to 1.8 million tonnes of steel ingot capacity. The expansion includes additions to existing facilities as well as establishment of new units. The new units proposed are the electrolytic tinning line, the continuous galvanizing line, the electrical sheet mill, and the special steel plate plant. A majority of the expansion units have been commissioned and the remaining units are likely to be commissioned by about the middle of 1968. The cost of expansion as sanctioned by Government sometime back and excluding township, mines etc. amounted to Rs. 1,125.6 million. This is, however, likely to go up considerably for a number of reasons including provision for additional items, effect of devaluation, increases in customs duties etc. etc.

EXPORT OF PEACOCK FEATHERS

4374. SHRI SHIVA CHANDRA JHA : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether India exports peacock feathers to foreign countries;

(b) if so, the quantities exported annually to each country during the last 5 years; and

(c) the annual foreign exchange earned therefrom ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) Yes, Sir

(b) and (c). A statement is laid on the Table of the House. [Placed in the Library. See No. Lt-508/68].

ISSUE OF LICENCES TO BIRLAS

4375. SHRI SHIVA CHANDRA JHA : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) for how many and for which new industries the Birlas have applied to Government for licences during the last six months; and

(b) how many and for which industries new licences have been granted during the above period and the reasons therefor ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) During the six months, September, 1967 to February, 1968, five applications for the setting up of new industrial undertakings have been received from firms belonging to the Birla Group. The applications related to the following industries:—

- (1) Benzaldehyde,
- (2) Benzoic Acid,
- (3) Benzal Alcohol,
- (4) Benzyl Benaote,
- (5) Acrylonitrile Monomer,
- (6) Acetonitrile,
- (7) Hydrogen Cyanide,
- (8) Plant & Machinery for Synthetic Fibres,
- (9) Carpet Yarn,
- (10) Vanaspathi,
- (11) Soap, and
- (12) Glycerine.

(b) One, for Cotton Yarn Industry.

The party already hold a licence for the establishment of a new undertaking at Midnapur. The licence in question was issued to the party to expand their existing unit at Champdany in lieu of the licence for Midnapur which was surrendered.

माल गाड़ियों तथा माल गोदामों से सामान की चोरी

4376. श्री ओ० प्र० त्यागी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में मालगाड़ियों और माल गोदामों से कितने मूल्य के माल की चोरी हुई ; और

(ख) इस प्रकार की चोरी को रोकने के लिये और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) वर्ष यादों में खड़े माल गोदामों माल डिब्बों आदि से चुराये सहित गाड़ियों गये माल का से चुराये गये मूल्य माल का मूल्य

	रुपये	रुपये
1962-63	15,86,038	1,82,681
1963-64	12,57,801	1,58,030
1964-65	18,27,277	1,68,208
1965-66	15,08,691	1,69,958
1966-67	24,17,116	2,54,969

(ख) (i) रात वाली सभी गाड़ियों पर सशस्त्र पहरेदार की व्यवस्था को तेज करना,

(ii) सशस्त्र और शस्त्र रहित कर्मचारियों द्वारा महत्वपूर्ण यादों में चौबीसों घंटे गश्त लगाना ;

(iii) यादों, माल गोदामों और प्लेटफार्मों में अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए सुरक्षा की धाराओं को सख्ती से लागू करना ;

(iv) अपराध और अपराधियों के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठा करने और विस्तारण के लिए सादे कपड़ों वाले और अपराध आसूचना कर्मचारियों का सर्वोत्तम उपयोग ;

(v) जहां कहीं आवश्यक हो सुरक्षा सम्बन्धी बुनियादी जरूरतों की व्यवस्था करना, जैसे असुरक्षित यादों में बाड़ लगाना, रोशनी के पर्याप्त प्रबन्ध और निगरानी मीनारों की व्यवस्था करना ।

आदिवासी क्षेत्रों में उद्योग

4377. श्री गं० ख० दीक्षित : क्या औद्योगिक विकास तथा समन्वय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी क्षेत्रों में लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने की दृष्टि से इन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है,

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ; और

(ग) जिन क्षेत्रों में यह योजना सफल सिद्ध हुई है, उनके नाम क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समन्वय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां राज्य क्षेत्र में पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों में ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कई कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं ।

(ख) ये योजनाएं आकार तथा विस्तार में प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न होती हैं यद्यपि ये योजनाएं सामान्यतः प्रशिक्षण संस्थानों और उत्पादन केन्द्रों के रूप में होती हैं जिनका उद्देश्य आदिवासियों को तकनीकी प्रशिक्षण देकर उन्हें अपना व्यापार या व्यवसाय

चलाने अब्बवा उनमें सुधार करना है। तकनीकी प्रशिक्षण तथा मार्बदर्शन, रस्से बनाने, टोकरी बनाने, जूते बनाने, दर्जी का काम, तथा वस्त्र बनाना, बुनाई, कताई, चमड़ा कमाना, चमड़े का काम, बड़ई का काम, लोहारी का काम, हथकरघा दस्तकारी, चूना तथा कोयला आदि कामों में किया जाता है। प्रशिक्षण अवधि में प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को 20 से 50 रुपये मासिक अनुदान अथवा वजीफा दिया जाता है। कई मामलों में प्रशिक्षित कारीगरों को 2,500 रुपये की अंश पूंजी या उपकरणों के लिए अथवा प्रवन्ध के लिए 6,000 रुपये का अनुदान देकर उन्हें औद्योगिक समितियां बनाने के लिए सहायता दी जाती है।

इसके अतिरिक्त योजना आयोग द्वारा स्थापित 49 ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाओं में से 5 परियोजनाएं ऐसे क्षेत्रों में स्थापित की गई हैं जहां मुख्यतया आदिवासी रहते हैं।

(ग) पिछड़े वर्ग के लिए स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं मध्य प्रदेश में अधिक लोकप्रिय हुई हैं। राज्य सरकार ने 1966-67 में इन पर 11.20 लाख रु० खर्च किया और 1967-68 में यह खर्च 11.35 लाख रुपये होने की आशा है। मध्य प्रदेश में रेशम के कीड़े पालने का उद्योग अधिक लाभप्रद हुआ है क्योंकि इसमें अनुसूचित आदिम जातियों को काम मिलता है।

मध्य प्रदेश में बेल्लाडिल्ला में रेलवे लाइनों का बिछाया जाना

4378. श्री गं० च० दीक्षित : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में बेल्लाडिल्ला में जो रूसी विशेषज्ञ गये थे उन्होंने यह संकेत दिया था कि बेल्लाडिल्ला में लौह अयस्क के बड़े भण्डार मिलने की सम्भावना है और यह सुझाव दिया था

कि उस क्षेत्र में यथासम्भव शीघ्र रेलवे लाइनें बिछाई जानी चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री च० मु० गुनाचा) (क) और (ख) . रेलवे बोर्ड को ऐसे किसी सुझाव की जानकारी नहीं है। सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय मध्य प्रदेश में "बेल्लाडिल्ला" से है। बेल्लाडिल्ला में लौह अयस्क के बड़े भंडार हैं। 444 किलोमीटर लम्बी रेलवे लाइन बना कर इन भण्डारों को विशाखापत्तनम् से पहले ही जोड़ा जा चुका है।

मध्य प्रदेश में ग्रामोद्योग सहकारी समितियां

4380. श्री गं० च० दीक्षित : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में ग्रामोद्योग समितियां तथा ग्रामोद्योग आश्रम नामक कुछ संस्थाएं स्थापित की गई हैं तथा खादी ग्रामोद्योग आयोग ने इन संस्थाओं में काफी धन लगाया है :

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है तथा क्या ये संस्थाएं अब भी चल रही हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो कितनी संस्थाएं बन्द की गई हैं तथा उसके क्या कारण हैं।

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफ़ी कुरंशी) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

ALL INDIA RAILWAY UNGRADED ACCOUNTS CLERKS CONVENTION

4381. SHRI VISWANATHA MENON: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government have received a deputation of the representatives of All India Railway Ungraded Accounts Clerks Convention;

- (b) if so, what are their demands; and
(c) the action taken thereon ?

THE MINISTER OF RAILWAYS
(SHRI C. M. POONACHA): (a) Yes.

(b) The demands include withdrawing the proposal to introduce computers on Railways, merger of Scales of Pay of Accounts Clerks, Abolition of Appendix II-A examination, steps for avoiding stagnation at the maximum for the Clerks in the lowest grade, high Scales of Pay for Accounts Clerks, and confirmation on completion of three years continuous service.

(c) The demands have been examined and some of them have also been discussed by the Railway Board with both the Federations of Railway Labour.

DAKSHIN, RAILWAY EMPLOYEES' UNION,
ERANAKULAM BRANCH

4382. SHRI VISWANATHA MENON :
Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government have received resolutions passed on the 15th February, 1968 by the Dakshin Railway Employees' Union, Ernakulam Branch;

(b) if so, what are the demands put forward by the Union; and

(c) the action taken to redress their grievances ?

THE MINISTER OF RAILWAYS
(SHRI C. M. POONACHA): (a) Yes Sir.

(b) The resolution relates to certain local issues concerning the service conditions of employees like Provision of Quarters, Workmen's Train. Grant of Night Duty Allowance etc.

(c) These are matters purely within the competence of the Railway Administration.

QUARTERS FOR WORKERS AT
ERNAKULAM

4383. SHRI VISWANATHA MENON :
Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government have received requests for providing quarters for all the railway workers working at Ernakulam I. P. N. at their place of work; and

(b) if so, the action taken by Government thereon ?

THE MINISTER OF RAILWAYS
(SHRI C. M. POONACHA): (a) Yes.

(b) Out of a total staff of 79 (Essential 51 and non-essential 28), 28 essential staff have already been provided with quarters. Construction of 37 additional quarters has also been sanctioned at Irimbanam. In the meantime, staff occupying quarters in and around Ernakulam and working at Irimbanam have been allowed to retain quarters till they are provided with quarters at Irimbanam.

WORKMEN SPECIAL TRAIN AT
ERNAKULAM.

4384. SHRI VISWANATHA MENON :
Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Railway Administration have taken steps to cancel the workmen special train at Ernakulam I. P.N., and

(b) if so, whether any alternate arrangement has been made by the authorities for the conveyance of workers who are not provided quarters at I.P.N. ?

THE MINISTER OF RAILWAYS
(SHRI C.M. POONACHA): (a) Yes.

(b) No alternative arrangements have been found feasible but it is proposed to reintroduce the special train as and when sanction of the Additional Commissioner of Railway Safety, which has been applied for, is received.

गैर-सरकारी पूंजी निवेश

4385. श्री भारत सिंह चौहान : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में गैर-सरकारी पूंजी निवेश के लिये कोई प्रोत्साहन नहीं है;

(ख) क्या देश में गैर-सरकारी पूंजी निवेश पर लाभ बढ़ाने तथा औद्योगिक

क्षमता का उपयोग करने के लिये कोई योजना बनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) बी, नहीं ।

(ख) और (ग) : स्थापित औद्योगिक क्षमता का पूरा इस्तेमाल करने और विनियोजन पर उचित लाभ की व्यवस्था करने के लिये सरकार द्वारा लगातार समीक्षा की जा रही है ।

INDUSTRIES TO BE SET UP IN ANDHRA PRADESH

4386. SHRI GADILINGANA GOWD : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) the industries proposed to be set up in Andhra Pradesh during the Fourth Five Year Plan in the Public Sector; and

(b) the estimated cost thereof ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F.A. AHMED) : (a) and (b). The work on the Fourth Plan, which is to begin from April, 1969, has just been initiated. A view of the programme of industries to be established in the Public Sector would be available when the detailed studies on the Fourth Plan are completed.

ONGOLE-HYDERABAD RAILWAY LINE

4387. SHRI GADILINGANA GOWD : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have received a proposal from the Government of Andhra Pradesh suggesting a new railway line between Ongole and Hyderabad via Nagarjunasagar; and

(b) the period for which this proposal is pending and the decision taken by Government thereon ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C.M. POONACHA) : (a) Yes.

(b) The proposal was recommended by the Andhra Pradesh Government in 1960 for inclusion in the III Five Year Plan. The funds for construction of new railway lines in the Fourth Plan are likely to be very limited out of which several throw-forward works from Third Plan and various priority projects required on strategic considerations, for industrial development, ore exploitation schemes etc., will have to be accommodated. As such this proposal will have to wait for better times for consideration.

DELICENSING OF INDUSTRIES

4388. SHRI GADILINGANA GOWD : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) the industries delicensed during 1967-1968 under the Industries (Development and Regulation) Act 1951; and

(b) whether there is any proposal to delicense all the industries connected with agricultural machinery and implements in view of their shortage in the country ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F.A. AHMED) : (a) Only 'wheeled agricultural tractors and power tillers' industry has been delicensed during 1967-68 under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951.

(b) No such proposal is at present under consideration of the Government.

DECENTRALISATION OF INDUSTRIES

4389. SHRI G.Y. KRISHNAN : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government propose to effect decentralisation of industry on district-wise basis; and

(b) whether Government also propose to appoint a Technical Committee consisting of the Members of Parliament to make a study of the feasibility of the scheme ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F.A. AHMED) : (a) Decentralisation of industry through the wide-spread development of village and small industries is an accepted policy of the Government but there is no proposal to effect decentralisation of industry on district-wise basis.

(b) No, Sir.

AGRO-INDUSTRIES

4390. **SHRI G.Y. KRISHNAN :** Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up agro-industries on district-wise basis to develop and promote agricultural production;

(b) if so, the types of agro-industries proposed to be set up; and

(c) whether there are any agro-industries functioning in the country and if so, how many and of what type, and where these are located ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F.A. AHMED) : (a) and (b). No. However, Agro-Industrial Corporations have been set up in the States of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Haryana, Maharashtra, Madras, Punjab, Orissa, Mysore and Uttar Pradesh. The main functions of these Corporations are :—

- (i) promotion and execution of industries having a bearing on production, preservation and supply of food;
- (ii) enabling persons engaged in agricultural and allied pursuits to own the means of modernising their operations;
- (iii) distribution of agricultural machinery and implements as well as equipment pertaining to processing, dairy, poultry, fishery and other industries connected with agriculture;
- (iv) undertaking or assisting in the efficient distribution of inputs for agriculture; and

(v) providing technical guidance to farmers and persons concerned with agro-industries with a view to enabling efficient conduct of their enterprise.

(c) There are already many units in different parts of the country engaged in the manufacture of different types of agro-based products. The total of such units is 325 approximately in the organised sector. The industries included are fruit & vegetable products, cereal products, fish products, dairy products, starch and dextrose and cashew processing.

FOREIGN COMPANIES

4391. **SHRI JUGAL MONDAL :** Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) the names and addresses of foreign companies which have established their monopoly in India in the field of jute, engineering, paper, aluminium and steel;

(b) the amount of foreign exchange sanctioned to these companies for the expansion of their industries during 1966-67 and 1967-68; and

(c) the steps taken by Government to encourage the Indians to set up such industries in the country ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F.A. AHMED) : (a) The Monopolies Inquiry Commission in statement 2 of their Report, laid on the Table of the House on 8-12-1965; gave a list of top five enterprises in respect of various individual products under different industrial groups. A list of foreign companies figuring therein in respect of jute, engineering, paper, aluminium, iron & steel, grouped under broad headings, is laid on the Table of the House. [Placed in library See No. L. T. 509/68]

(b) The information for the years 1966-67 and 1967-68 is not available.

(c) Attention is invited to the Industrial Policy Resolution 1949 and 1956 and the Provisions of Industrial (Development and Regulation) Act and regulations made thereunder.

रेलवे में स्वचालित मशीनें

4392. श्री मधु लिमये : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के मद्रास कार्यालय तथा कुछ अन्य कार्यालयों में स्वचालित मशीनें लगाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उसकी संख्या कितनी है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं तथा कितने लोग रोजगार पाने की सम्भावनाओं से वंचित हो गये हैं;

(घ) क्या रेलवे कर्मचारियों ने इन मशीनों के लगाये जाने का विरोध किया था; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चं० मु० पुनाचा) :

(क) और (ख) . भारतीय रेलों में आठ संगणक लगाये गये हैं अर्थात् उत्तर, मध्य, पश्चिम, दक्षिण (मद्रास) और दक्षिण-पूर्व रेलों और सवारी डिब्बा कारखाना, पेरम्बूर, डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी और चित्तूरंजन रेल इंजन कारखाना में एक-एक ।

(ग) कोई व्यक्ति बेकार नहीं हुआ है । संगणक लगाये जाने से नियोजन पर अब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ा है । संगणकों के इस्तेमाल के कारण यदि लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की संख्या में कमी करनी पड़े तो भी भविष्य में कुल मिलाकर रेलों की नियोजन संभाव्यता पर कोई खास असर पड़ने की संभावना नहीं है ।

(घ) और (ङ) कुछ अभ्यावेदन मिले थे । श्रमिक संगठनों को यह सूचित कर दिया गया है कि सेवा-रत कर्मचारियों के हित पूर्णतः सुरक्षित हैं क्योंकि इसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों की कोई छटनी

नहीं की जायेगी; 20 अगस्त, 1966 को उनकी पदोन्नति की जो संभावनायें थीं, उन्हें अक्षण रखा जायेगा और यदि संगणकों के इस्तेमाल के कारण किसी कर्मचारी को, उसके वर्तमान कार्य से हटाकर किसी दूसरे पद पर लगाया जायेगा, तो उसकी सहमांत के बिना उसे किसी दूसरे स्टेशन पर स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा ।

कटनी स्थित आयुध कारखाने के निकट रेलवे का उपरि पुल

4393. श्री रामावतार शर्मा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कटनी स्थित आयुध कारखाने का एक सुरक्षा अधिकारी रेलवे लाइन को पार करते समय रेलगाड़ी के नीचे आ गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस कारखाने के कर्मचारियों ने वहां एक उपरी पुल बनाये जाने की अपनी मांग मनवाने के लिये हड़ताल कर दी है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस कारखाने के निकट एक उपरी पुल बनाने का सरकार का विचार है, और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चं० मु० पुनाचा) :

(क) 14-2-1968 को, जब आर्डिनेन्स फॅक्टरी, कटनी का एक कर्मचारी आर्डिनेन्स फॅक्टरी के पास स्थित समपार फाटक पर लाइन को पार कर रहा था तो वह गाड़ी नं० 27 डाउन काशी एक्सप्रेस के नीचे आ गया ।

(ख) जी नहीं । लेकिन कारखाने के कामगारों ने उपरी पुल की मांग पर जोर दिया था ।

(ग) और (घ) कटनी साउथ स्टेशन पर स्थित समपार फाटक, जिससे होकर आर्डिनेन्स फैंक्टरी को भी रास्ता जाता है, की जगह ऊपरी पुल बनाना व्यावहारिक होगा। नियमतः वर्तमान व्यस्त समपारों की जगह रेलवे लाइन के ऊपर-नीचे सड़क पुलों के निर्माण के प्रस्ताव सम्बन्धित राज्य सरकार/सड़क प्राधिकारी की ओर से आने चाहिए, जिनमें यह बताया जाना चाहिए कि कार्य को कितनी अग्रता अपेक्षित है और सड़क प्राधिकारी अपने खर्च पर ढलबा पहुंच-मागों से सम्बन्धित निर्माण-कार्य किस वर्ष शुरू करेगा।

जहां तक कटनी साउथ स्टेशन के समपार की जगह ऊपरी सड़क पुल बनाने की योजना का सम्बन्ध है, न तो राज्य सरकार और न आर्डिनेन्स फैंक्टरी के अधिकारियों की ओर से कोई पक्का प्रस्ताव मिला है।

EX-CADRE POSTS IN THE RAILWAY BOARD'S OFFICE

4394. SHRI YASHPAL SINGH : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the number of ex-cadre posts in the Railway Board's office as on 1st January, 1968;

(b) the mode of selection to such posts

(c) whether any representations have been received against appointments to such ex-cadre posts of all cadres in different Directorates from the Railway employees; and

(d) if so, the action taken thereon.

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C.M. POONACHA) : (a) 271. Bulk of these posts are required to be filled by technical personnel with extensive background of railway work.

(d) Selections for filling such posts are generally made from amongst the eligible railway staff or those in the Board's office, on the basis of the recommendations of the Selection Committees constituted for the purpose. In the case of gazetted posts,

such selections are made in terms of approved recruitment rules and procedures.

(c) Yes. A few.

(d) Each such representation was duly examined to see if any change was called for in the existing position.

RAILWAY SERVICE COMMISSIONS

4395. SHRI YASHPAL SINGH : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the method of appointing the Chairman and Members of the different Railway Service Commissions;

(b) the terms of reference and condition of service of the Chairmen;

(c) whether any extension has been given to the present incumbent of the post of Chairman of the Allahabad Railway Service Commission; and

(d) if so, the period thereof ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C.M. POONACHA) : (a) Chairmen and Members of Railway Service Commissions are appointed on the recommendation of the Union Public Service Commission;

(b) The Chairman is the administrative head of the Railway Service Commission entrusted with the task of recruitment of Class III staff for Railways.

The tenure of appointment of Chairman is for a period of four years from the date of appointment or the date of attainment of the age of 62, whichever is earlier. The scale of pay for the post is Rs. 1800/- p.m. (fixed);

(c) No;

(d) Does not arise.

UNDER AND OVER-BRIDGES IN M.P.

4396. SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the names of places where the construction of under and over-bridges was taken up in 1967-68 in Madhya Pradesh;

(b) the number out of them which have been completed; and

(c) the places where the construction of under and over-bridges would be taken up in 1968-69 in Madhya Pradesh ?

THE MINISTER OF RAILWAYS
(SHRI C.M. POONACHA) : (a) Nil.

(b) Does not arise.

(c) Two road over-bridges, one at Indore and the other on Pendra-Chirimiri Road are proposed to be taken up in 1968-69.

PASSENGER TRAINS

4397. SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the number of passenger trains running on Delhi—Calcutta, Delhi—Madras, Delhi—Bombay, Bombay—Madras, Calcutta—Madras and Bombay—Calcutta lines; and

(b) the number out of them which were introduced after 1950 on each section separately?

THE MINISTER OF RAILWAYS
(SHRI C. M. POONACHA) (a) and (b).
The information is furnished below:-

Route	No. of through trains each way (other than sectional services) running at present	No. of introduced after 1960
(i) Delhi-Calcutta		
{ via Main line	4	..
{ via Grand Chord	2	1
(ii) Delhi-Madras	3	2
(iii) Delhi-Bombay		
{ via Western Rly.	4	2
{ via Central Rly.)	2	..
(iv) Bombay-Madras	4	2
(v) Calcutta-Madras	4	3

(vi) Bombay-Calcutta

{ Via Nagpur	3	2
{ Via Allahabad	2	1

GOODS LOST FROM KATNI AND ITARSI YARDS

4398. SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the total value of goods lost from Katni and Itarsi yards during 1967;

(b) the number of wagons received in the above yards and the number out of them detained for 4 days or over, separately for each yard;

(c) whether complaints of unauthorised detention of wagons in these yards have been received; and

(d) if so, the action taken thereon?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA) (a) Rs. 884/-

(b) Total number of wagons received Number of wagons detained for 4 days and over

	1966	1967	1966	1967
New Katni Yard	4,38,718	4,29,057	4,284	4,740
New Itarsi Yard	7,42,384	7,60,258	3,153	3,203

(c) No.

(d) Does not arise.

LOSS ON SIMLA-KALKA AND METTUPALAYAM OOTACAMUND LINES

4399. SHRI NANJA GOWDER: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state the loss incurred on the Simla-Kalka and the Mettupalayam-Ootacamund lines separately during the last three years ending 31st March 1967?

THE MINISTER OF RAILWAYS
(SHRI C. M. POONACHA): The required

information is furnished below:-

(Rs. in lakhs)

Name of line	Loss including interest on capital		
	1964-65	1965-66	1966-67
Simla-Kalka	31.18	39.21	Being collected and will be laid on the table of the House.
Mettupalayam-Ootacamund	28.01	31.39	34.87

रेलवे कर्मचारियों को क्वार्टरों का आवंटन

4400. श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी रेलवे में पटना, गया, धनबाद और जमालपुर में दस वर्ष से अधिक अवधि की नौकरी पूरी करने के बाद भी बहुत से रेलवे कर्मचारियों को अभी तक क्वार्टर नहीं मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो इन शहरों में ऐसे कर्मचारी कितने हैं;

(ग) इनको क्वार्टर न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) उन्हें कब तक क्वार्टर दे दिये जायेंगे ?

रेलवे मंत्री (श्री जे० मु० पुनाच्चा) :

(क) से (घ). सूचना मंगायी जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

रेलवे अधिकारियों को तीसरी श्रेणी के क्वार्टरों का नियतन

4401. श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ रेलवे

अधिकारी अब भी तीसरी श्रेणी के क्वार्टरों में रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन अधिकारियों को उसी श्रेणी के क्वार्टर देकर, जिस श्रेणी के लिये वे हकदार हैं, उनसे तीसरी श्रेणी के क्वार्टर कब तक खाली करवाये जायेंगे ?

रेलवे मंत्री (श्री जे० मु० पुनाच्चा) :

(क) जी हां ।

(ख) (1) अधिकारियों के क्वार्टरों की कमी,

(2) कुछ अधिकारियों को उनकी तीसरी श्रेणी से पदोन्नति के पूर्व क्वार्टर दिये गये थे । उंचे दर्जे के जिस टाइप के क्वार्टरों के ये अधिकारी हकदार हैं, उनकी कमी के कारण उन्हें वर्तमान क्वार्टरों में बने रहने की अनुमति देनी होगी ।

(ग) इसके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती । जैसे-जैसे अधिकारियों के उपयुक्त टाइप के क्वार्टर सुलभ होते जाते हैं, उनसे टाइप 3 के क्वार्टर खाली करा लिये जाते हैं ।

रेलवे कर्मचारियों को क्वार्टरों का आवंटन

4402. श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे कर्मचारियों को प्रति वर्ष सामान्यतया कितने क्वार्टर आवंटित किये जाते हैं;

(ख) प्रति वर्ष कितने क्वार्टर पारी से बाहर आवंटित किये जाते हैं; और

(ग) पारी से बाहर क्वार्टर किस आधार पर आवंटित किये जाते हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री शे. मू. पुनचा) :

(क) कर्मचारियों को हर वर्ष कितने क्वार्टर आवंटित किये जायें, यह वर्ष के दौरान बन कर तैयार होने वाले क्वार्टरों की संख्या पर निर्भर होता है और क्वार्टरों का निर्माण इस बात पर निर्भर है कि वर्ष में इसके लिए कितना धन उपलब्ध है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगभग 70,913 क्वार्टर बनाये गये थे। वर्ष 1967-68 में, 9,266 क्वार्टर और तैयार होने की संभावना है। इसके अलावा, कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति, मृत्यु, स्थानान्तरण आदि के कारण खाली होने वाले क्वार्टर भी प्रतीक्षा सूची-गत कर्मचारियों को उनके रजिस्ट्रेशन के क्रम के अनुसार आवंटित किये जाते हैं।

(ख) कुछ प्रतिशत क्वार्टर पारी-से-बाहर आवंटन के लिए अलग रखे जाते हैं।

(ग) पारी-से-बाहर क्वार्टर आवंटित करने के लिए कोई कसौटी नहीं रखी गयी है। लेकिन दिक्कत होने पर, जैसे किसी कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य की लम्बी बीमारी की हालत में, हर मामले के सापेक्ष गुण-दोष के आधार पर ऊपर (ख) में बताये गये क्वार्टरों में से क्वार्टर आवंटित किये जाते हैं।

इसके अलावा, यदि किसी रेल कर्मचारी को रेलवे क्वार्टर आवंटित हो और वह सेवा-निवृत्त हो जायें या सेवा में रहते हुए मर जायें तो उसके पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति/पिता को पारी-से-बाहर सर्वोच्च अप्रता के आधार पर क्वार्टर आवंटित कर दिया जाता है। लेकिन शर्त यह है कि निवृत्त/मृत कर्मचारी का उक्त सम्बन्धी रेल कर्मचारी हो, और रेलवे क्वार्टर पाने का पात्र हो और निवृत्त होने वाले या मृत कर्मचारी की निवृत्ति या मृत्यु की तारीख से पहले कम से कम छः महीने उसके साथ क्वार्टर में रहा हो।

REDUCTION IN POSTS OF ASSISTANT STATION MASTERS AND STATION MASTERS ON N.F. RAILWAY

4403. SHRI B. K. DASCHOWDHURY: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that reduction has been made in the posts of Station Masters and Assistant Station Masters in D Section of North-East-Frontier Railway;

(b) if so, the number of posts reduced;

(c) whether any representation has been received from the Station Masters' Association against the reduction of posts; and

(d) if so, the steps taken by Government in the matter?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) and (b). No; but four posts of Station Masters in the particular Section have been down-graded to those of Assistant Station Masters.

(c) and (d). A representation against the down-gradation has been received. The matter is being examined.

राज्य व्यापार निगम को आयात लाइसेंस देना

4404. श्री मोलहू प्रसाद : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि आयात लाइसेंस देने के मामले में इस बात को ध्यान में नहीं रखते हुए कि राज्य व्यापार निगम को किसी क्षेत्र विशेष का अनुभव है अथवा नहीं, उक्त निगम को प्राथमिकता दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे लाइसेंसों पर राज्य व्यापार निगम द्वारा औसतन कितने प्रतिशत कमीशन वसूल किया जाता है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क) तथा (ख)-जानकारी एकत्र की जा रही है और सप्ताह पटल पर रख दी जायेगी।

अमोनियम सल्फेट का आयात

4405. श्री मोलह प्रसाद : क्या वाणिज्य मंत्री 7 जुलाई, 1967 के अतारंकित प्रश्न संख्या 4961 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड के आयात पर खर्च की जाने वाली भारी राशि को बचाने के लिये कोई स्थानानापन्न पदार्थ ढूँढने का सरकार का विचार है;

(ख) क्या उर्वरकों के आयात पर प्रति वर्ष व्यय की जाने वाली लगभग 40 करोड़ रुपए की राशि किसानों को देकर उन्हें खाद के रूप में गोबर का प्रयोग करने के लिये प्रेरित करने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरंशी) : (क) जी, हां। सरकार यूरिया, नाइट्रो-फास्फेट क्लेशियम अमोनियम नाइट्रेट आदि नाइट्रोजनमय उर्वरकों के और पोटेशियम क्लोराइड तथा पोटेशियम शोनाइट के, जो अमोनियम सल्फेट तथा पोटेशियम क्लोराइड के लिये स्थानापन्न पदार्थों के रूप में काम में लाये जा सकेंगे, उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने का प्रयत्न कर रही है।

(ख) तथा (ग) : कम्पोस्ट के उत्पादन के लिये गोबर और पशुशालाओं तथा खेतों के अन्य कूड़े का पूर्ण उपयोग करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में कम्पोस्ट उत्पादन के लिये स्थानीय खाद सम्बन्धी साधनों के विकास तथा उपयोग की एक योजना अखिल-भारतीय आधार

पर चल रही है। यह केन्द्रीय सहायता-प्राप्त राज्य योजना है, जिसमें योजना अवधियों के दौरान निरन्तर प्रगति होती रही है।

गोमांस और बछड़े के चमड़े का निर्यात

4406. श्री मोलह प्रसाद : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में कितने मूल्य के गोमांस और बछड़े के चमड़े का निर्यात किया गया;

(ख) क्या देश में दूध और दूध से बनने वाले पदार्थों की कमी को दूर करने तथा किसानों के लिये अच्छे बछड़े उपलब्ध कराने के लिये गोमांस और बछड़े के चमड़े के निर्यात पर सरकार का प्रतिबन्ध लगाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरंशी) : (क) 1962-63 से 1967-68 (नवम्बर, 67) तक गो-जातीय पशुओं के मांस तथा बछड़े के चमड़े के निर्यात का मूल्य संलग्न विवरण 'क', 'ख'-1 तथा 'ख'-2 में दिया गया है। जो सभा पटल पर रखा गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या Lt 510/68]।

(ख) तथा (ग) . गोमांस के निर्यात पर तो पाबंदी है, तथापि बछड़े के चमड़े के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाना वांछनीय नहीं समझा जाता क्योंकि यह विदेशी मुद्रा कमाने की एक महत्वपूर्ण मद है।

CEMENT FACTORY AT BOKAJAN (ASSAM)

4407. SHRI R. BARUA: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have accorded approval for the establishment of a cement factory at Bokajan in Assam in the public sector; and

(b) if so, the capital investment in the project and its production capacity?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F.A.AHMED): (a) and (b). A proposal for setting up a cement factory in the public sector with a capacity of 200,000 tonnes per annum at an estimated capital cost of Rs. 858 lakhs at Bokajan is under consideration of the Government.

CLOSURE OF KHADI GRAMODYOG BHAVANS

4408. SHRI S. A. AGADI: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some Gramodyog Bhavans run by the Khadi & Village Industries Commission are being closed in the country;

(b) if so, the reasons therefor and the names of the agencies to which the Bhavans are being handed over; and

(c) the terms and conditions of such Agency arrangements

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) Khadi & Village Industries Commission does not propose to close any Bhavans.

(b) and (c). Do not arise.

राजस्थान और मध्य प्रदेश में घड़ियों के कारखाने

4409. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राजस्थान के एक उद्योगपति को मध्य प्रदेश और राजस्थान में घड़ियों के कारखाने स्थापित करने की अनुमति दी है;

(ख) क्या यह भी सच कि सरकार ने इस सम्बन्ध में एक विदेशी कम्पनी को अनमति दी है, और

(ग) यदि हां, तो ये कारखाने कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

HINDUSTAN STEEL LIMITED

4410. SHRI M. SUDARSANAM: Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to have a Functional Board at the Hindustan Steel Ltd.; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STEEL, MINES AND METALS (DR. CHANNA REDDY) (a) and (b). Yes, Sir. It is proposed to strengthen the Board of Directors of Hindustan Steel Ltd.; which now consists of only one full-time Director, namely, the Chairman, by adding a few more full-time Directors.

FOREIGN COLLABORATIONS

4411. SHRI S. R. DAMANI: SHRI R. BARUA:

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have finalised the policy resolution on foreign collaborations:

(b) if so, whether the resolution will define the areas and terms of foreign investment;

(c) whether any separate body is proposed to be created to implement it ; and

(d) the items in which majority participation by the foreign investors will be allowed.

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) No. Sir.

(b) to (d). Do not arise.

EXPORT-ORIENTED SPINNING MILLS

4412. SHRI VASUDEVAN NAIR: Will the Minister of COMMERCE be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1699 on the 24th November, 1967 regarding export-Oriented Spinning mills and state:

(a) whether Government have since taken any final decision on the setting up of Export-Oriented Spinning mills; and

(b) if so, the number of mills proposed to be established and their likely locations?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

दानापुर स्थित पूर्व रेलवे बायज हाई स्कूल के अध्यापकों की ओर से ज्ञापन पत्र

4413. श्री रामावतार शास्त्री : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दानापुर स्थित पूर्व रेलवे बायज हाई स्कूल के सत्रह अध्यापकों ने 14 सितम्बर, 1966 को रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को एक ज्ञापन पत्र भेजा था; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया ?

रेलवे मंत्री (श्री जे० मु० पुनाचा): (क) ऐसा कोई ज्ञापन देखने में नहीं आया है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

Small Car Project.

4414. SHRI VIRENDRA KUMAR SHAH :
SHRI DEORAO PATIL

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is fact that the Planning Commission propose to shelve the small car Project again; and

(b) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F.A. AHMED) : (a) and (b). The Planning Commission, who were recently consulted to ascertain the availability of resources for the small car project, have not yet indicated their final views.

बैलाडिल्ला (मध्य प्रदेश) में इस्पात कारखाना

4415. श्री नाथूराम अहिरवार : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में बैलाडिल्ला में इस्पात कारखाना स्थापित करने के लिए कोई योजना बनाई गई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त कारखाने के बारे में प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य भी पूरा हो चुका है; और

(ग) उपरोक्त कारखाने का निर्माण कार्य आरम्भ न किये जाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० जन्ना रेड्डी) : (क) से (ग) . सरकार ने नये स्थानों पर लोहे और इस्पात के नये कारखाने स्थापित करने के उद्देश्य से कई शक्यता प्रतिवेदन प्राप्त किये हैं। इनमें बैलाडिल्ला क्षेत्र भी शामिल है, परन्तु लोहे और इस्पात की कुल मांग तथा सारे देश के विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए उपलब्ध साधनों को देखते हुए अभी इस मामले पर अन्य प्रायोजकों के साथ विचार किया जाना है।

33 अप रेल गाड़ी के साथ लगाया जाने वाला शयन डिब्बा

4416. श्री रामावतार शर्मा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्दौर से बिलासपुर के लिये चलने वाली 33 अप रेल गाड़ी के साथ लगाये जाने वाले शयन डिब्बे में केवल 32 स्थानों की व्यवस्था है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये स्थान यात्रियों की आवश्यकता पूरी करने के लिये सर्वथा अपर्याप्त है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस शयन डिब्बे के लगाये जाने से पहले इस गाड़ी में 75 स्थानों की व्यवस्था थी;

(घ) यदि हां, तो 75 स्थानों वाले शयन डिब्बे को हटाये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार यात्रियों की असुविधा को देखते हुए 75 स्थानों वाला डिब्बा लगाने का है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) जी नहीं। इस गाड़ी में तीसरे दर्जे की 56 शायिकाएं हैं अर्थात् तीसरे दर्जे के आंशिक तीन टियर शयन-यान में 32 और तीसरे दर्जे के दो टियर शयन-यान में 24।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां।

(घ) 75 शायिकाओं वाले डिब्बे का पूरा उपयोग नहीं हो रहा था।

(ङ) जी नहीं, क्योंकि 56 शायिकाओं वाले वर्तमान डिब्बे से मांग पर्याप्त रूप से पूरी हो जाती है।

मध्य रेलवे के टिकट निरीक्षकों को ऊनी बर्दियां

4417. श्री रामावतार शास्त्री : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर, पश्चिम और पूर्वोत्तर रेलवे के टिकट निरीक्षकों को ओवर कोट समेत ऊनी बर्दी दी जाती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह सुविधा मध्य रेलवे के टिकट निरीक्षकों को नहीं दी जाती है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) ओवरकोट एक 'हिफाजती पहिरावा' है जिसका मानकीकरण नहीं किया गया है और हर रेलवे स्थानीय परिस्थिति के अनुसार उसकी व्यवस्था करती है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की घड़ियों के मूल्य

4418. श्री रामावतार शास्त्री : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने अपनी जनता, सिटीजन, सुजाता तथा अन्य घड़ियों के मूल्य बढ़ा दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो कितने और इसके क्या कारण हैं?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) : इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन द्वारा माड़ा बढ़ा दिये जाने के फलस्वरूप हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने अपनी घड़ियों की कीमतों में उतनी ही वृद्धि कर दी। काफी बातचीत के पश्चात् इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन ने यह वृद्धि समाप्त कर देने के लिए सहमत हो गया है। बढ़े हुए मूल्य नवम्बर, 1967 के मध्य से मार्च, 1968 के मध्य तक लागू रहे हैं। अब घड़ियां पुराने मूल्यों पर बेची जा रही हैं।

पूर्वोत्तर रेलवे यात्री सुरक्षा परिषद्

4419. श्री रामावतार शास्त्री : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे यात्री सुरक्षा परिषद् ने अपनी पन्द्रह-सूत्री मांगों के सम्बन्ध में उनके नाम एक पत्र भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चं० मु० पुनाचा) :

(क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है । [पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या LT-511/68] ।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

COLLABORATION FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN CEYLON

4422. SHRI S.R. DAMANI :
SHRI MANIBHAI J. PATEL :

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Ceylon has asked for technical and financial collaboration for its industrial development;

(b) if so, the main features thereof; and
(c) Government's reaction thereto?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : (a) No, Sir.

(b) and (c) . Do not arise.

CEMENT ALLOCATION AND CO-ORDINATING ORGANISATION

4423. SHRI JUGAL MONDAL : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to starred Question No. 167 on the 20th February, 1968 and state :
M18 LSS(CP)68-6.

(a) whether the enquiry against the Cement Allocation and Co-ordinating Organisation has since been completed; and

(b) if so, the main features thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F.A. AHMED) : (a) The matter is under examination.

(b) Does not arise.

PRICE OF PAPER

4424. SHRI MAHANT DIGVIJAI NATH : Will the Minister of Industrial DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 155 on the 20th February, 1968 and state :

(a) whether any decision has since been taken about the price of paper; and

(b) if so, the main feature thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (a) Not yet, Sir.

(b) Does not arise.

NEW INDUSTRIES IN U. P.

4425. SHRI MAHANT DIGVIJAI NATH : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to State:

(a) the number and nature of new industries started in Uttar Pradesh during the last five years;

(b) whether the industrial development of the state is proceeding according to the schedule;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) the new industries proposed to be set up in the near future in the State in the public and private sectors?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

इंग्लैण्ड, रूस और पश्चिम जर्मनी से आयात तथा उनको निर्यात

4426. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1967 से अब तक भारत द्वारा रूस, अमरीका, इंग्लैण्ड तथा पश्चिम जर्मनी से किन किन वस्तुओं का आयात किया गया है तथा कितनी मात्रा में;

(ख) वर्ष 1968-69 में इन देशों को किन किन वस्तुओं का निर्यात किया जायेगा; और

(ग) उससे कितनी विदेशी मुद्रा कमाई जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफ़ी कुरैशी) : (क) एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा पटल पर रखा गया है। [पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या LT-512/68]।

(ख) 1968-69 में सोवियत रूस, सं०रा० अमरीका, ब्रिटेन, ५० जर्मनी को उनकी आवश्यकतानुसार सभी अनुमेय मर्दों का निर्यात किया जा सकता है।

(ग) 1968-69 में कमायी जाने वाली विदेशी मुद्रा का ठीक ठीक अनुमान लगाना संभव नहीं है।

MANUFACTURE OF BATTERY CELLS

4427. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number, names, places and addresses of foreign and Indian owned factories manufacturing Battery Cells in India with Capital investments;

(b) the names of Directors, details of foreign collaboration, if any, of each unit, the names and particulars of products, with their quantity and value, produced by each unit annually during the last five years; and

(c) the value of Battery cells exported annually with the names of countries during the above period by each unit?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (a) to (c). The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

EMPLOYEES IN THE FACTORIES MANUFACTURING BATTERY CELLS

4428. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of employees and annual wage bill of the Companies manufacturing Battery Cells, Company-wise; and

(b) the number of foreigners employed, their salaries and their annual remittances overseas, company-wise?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (a) and (b). The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

PROFITS BY COMPANIES MANUFACTURING BATTERY CELLS

4429. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to State :

(a) the amount of profits remitted to foreign countries during the last 5 years by the foreign-owned Battery Cells manufacturing Companies; and

(b) the amount of foreign exchange allowed annually during the above period to each unit and particulars of items imported with their specific purpose?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (a) and (b). The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

**NATIONAL COAL DEVELOPMENT
CORPORATION**

4430. SHRI C.C. DESAI : Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to state :

(a) whether the off-take of coal of the National Coal Development Corporation, Dhanbad, remained static at 9.156 lakh tonnes in January, 1968 as against 9.165 lakh tonnes in December, 1967, owing to the embargo imposed on its movement by the Railways;

(b) whether it is a fact the pit-head stocks went up from 10.106 lakh tonnes at the end of December, 1967 to 10,663 lakh tonnes at the end of January, 1968;

(c) whether the Corporation has shown a financial loss during 1967-68 despite higher production of coal this year;

(d) whether the Budget prepared for 1968-69 stipulates substantial losses together with considerable increases in capital cost of different projects currently undertaken by the National Coal Development Corporation; and

(e) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL, MINES AND METALS (SHRI P. C. SETHI) : (a) and (b). It is not a fact that off-take of coal of National Coal Development Corporation remained static owing to the embargo imposed on its movement by the Railways. However, both production and despatches were affected on account of shortfall in wagon supply in certain areas. Consequently, despatches in January, 1968 were 8.91 lakh tonnes as against 8.94 lakh tonnes in December, 1967. As a result the pit-head stocks which stood at 10,10,665 tonnes on 31-12-67 went upto 10,67,132 tonnes on 31-1-68.

(c) It is not possible at this stage to indicate whether the Corporation will suffer financial loss or earn profit during this year.

(d) and (e). Budget proposals for 1968-69 do not indicate substantial losses. However, cases have come to notice where the capital cost on certain projects had exceeded

the original project estimates. This excess is due mainly to (i) increase in wages and cost of materials, (ii) changes in design and specification (iii) modification of original project reports/estimates, and (ic) increase the cost of imported equipment and spares as a result of devaluation.

NON-AVAILABILITY OF COAL

4431. SHRI C. C. DESAI : Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many consumers of fuel have resorted to fuel oil despite its being costlier because of non-availability of good quality coal;

(b) whether this would be detrimental to national interest because of India's inability to meet the entire demand of fuel oil inoigenously resulting in substantial import from abroad;

(c) whether Government propose to use more of coal till India has a favourable balance of trade and restrict the use of fuel oil to certain specialised applications;

(d) whether it is also a fact that the Bihar State has increased the royalty rates on coal by another 50 paise per tonne; and

(e) if so, Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL, MINES AND METALS (SHRI P. C. SETHI) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No such specific proposal is under consideration. The use of different types of coal is governed chiefly by the comparative economics of utilisation of one *vis-a-vis* the other.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

RAILWAY STATION AT BHEJIPUT

4432. SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether any proposals have been received for opening a railway station at Bhejiput on the South-Eastern Railway in Orissa on the border of Ganjam and Puri District; and

(b) if so, the details thereof and when this station is proposed to be opened?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA) : (a) Yes.

(b) A proposal for providing a train halt at Bhejput at Kms. 538/8 from Howrah between Chilka and Khallikota stations on the Kharagpur-Waltar Section was received and examined in 1962. The proposal was not found feasible from engineering point of view as it involved heavy regrading of the track over a considerable length and affected some bridges. The proposal was, therefore, dropped.

**DIRECT TRAIN FROM DELHI TO
BHUBANESWAR**

4433. **SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI :** Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government are aware that there is no direct train service from Delhi to Bhubaneswar;

(b) whether Government propose to run Nilachal direct train service from Delhi to Puri ; and

(c) if so, when?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA) : (a) Yes.

(b) No.

(c) Does not arise.

RAILWAY OVER-BRIDGE NEAR SILCHAR TOWN

4434. **SHRIMATI JYOTSNA CHANDA :** Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether there has been a demand from public and the Members of Zonal Railway Users' Consultative Committee for a railway over-bridge near silchar town; and

(b) if so, the decision taken thereon?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA) : (a) Yes; the demand for a road over-bridge in Silchar town was tentatively made by the Government of Assam in November 1967.

(b) The Railways construct over/under-bridges in replacement of existing level crossings provided the schemes are spon-

sored by the State Government and provided the State Government/Road authority agree to bear their share of cost as per extant rules. The annual programme of works of over/under bridges is finalised in consultation with the state Government. The position has accordingly been explained by the Railway to the Government of Assam, whose final decision for the road over-bridge referred to, is still pending.

PRODUCTION OF NEWS-PRINT

4435. **SHRI K.M. KOUSHIK :** Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 80 per cent of the total requirement of news-print is being imported from foreign countries; and

(b) if so, the steps taken by Government to step up production of news-print in the country so that imports may be considerably lessened.

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (a) Yes, Sir.

(b) The following steps have been taken to development further capacity for the manufacture of news-print in the country;

(i) the newsprint industry has been from the licensing provisions of the Industries (Dev. and Regulation) Act, 1951.

(ii) Excise duty on newsprint has been abolished.

(iii) Capacity of the existing newsprint mill in the country is being increased from 30,000 to 75,000 tonnes per annum.

(iv) A feasibility Report for one news-print project in the public sector is under preparation.

(v) One newsprint mill is proposed to be set up by a private party in Himachal Pradesh, for which they are having negotiations with the Himachal Pradesh authority for supply of raw materials.

PRODUCTION OF NEWS PRINT

4436. SHRI K. M. KOUSHIK : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether there is any concern in the country which is manufacturing newsprint from bagasse and if so, what percentage of our requirement it is able to meet;

(b) whether there are any difficulties in the setting up of bigger units for the production of news-print from bagasse; and

(c) if so, what they are and the difficulties which lie in the way of setting up a number of units in view of the fact that that a lot of bagasse is being used as fuel?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) No, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) The following are some of the difficulties in setting up a News-print mill based on bagasse in the country :—

(i) The Sugar Mills find it economically and technically less attractive to release bagasse for paper/newsprint industries, as the bagasse at present is being used by them as a ready and cheap available fuel. The alternative fuels are Furnace oil and coal. The Furnace oil is more costly and it also requires replacement of the existing boilers. As regards coal, the Sugar Industry is apprehensive about its regular supply at economic prices.

(ii) The manufacture of newsprint from bagasse as main raw material on commercial scale has yet to be established in the world, and we shall have to take a calculated risk by venturing in this line.

(iii) By gradual decline in the cultivation of Sugar cane and its greater diversion to the manufacture of Gur and Khandesari, its availability to the Sugar Mills in the country has decreased. The supply position of bagasse for paper/newsprint industry in future has therefore become uncertain.

SEMINAR OF MACHINE TOOL MANUFACTURERS AND CONSUMERS

4437. SHRI K. M. KOUSHIK : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a seminar of the machine tool manufacturers and the consumers was held recently; and

(b) if so, the outcome thereof and Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (a) The seminar was held in August 1967 and was sponsored by Government.

(b) The requirements of machine tools of eleven projects, both in the public and private sectors, in the coming years were jointly discussed and it was found that a sizeable portion of these requirements could be met from indigenous sources. Follow-up action to secure orders for these machine tools is being taken by the machine tool manufacturers. The seminar was the first attempt to bring the manufacturers and consumers together and resulted in a mutual awareness of the potentialities and problems.

EXPORT OF MANGANESE ORES

4438. SHRI K. M. KOUSHIK : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Brazil is the only competitor in the export of manganese ore in the world market;

(b) if so, whether Government propose to hold any discussions with Brazil to adopt a common policy with regard to the prices and exports; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTRY IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : (a) No, Sir.

(b) Government propose to have discussions with Brazil and other interested exporting countries on common problems relating to export of manganese ore.

(c) Does not arise.

TRADE WITH ARAB COUNTRIES

4439. SHRI MANIBHAI J. PATEL : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Arab countries propose to boost trade with India;

(b) whether Government here received any proposals in this regard; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : (a) to (c) . The Arab countries have very friendly relations with India and would welcome further development of trade with us. The scope for this is under constant review in consultation with them.

No specific proposals have, however, been received by Government from Arab countries.

GRAPHITE CRUCIBLE PLANT

4440. SHRI V. NARASIMHA RAO : Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to start a Graphite crucible plant with foreign collaboration; and

(b) if so, the estimated cost of the plant and name of the foreign company ?

THE MINISTER OF STEEL, MINES AND METALS (DR. CHANNA REDDY) : (a) and (b) : The required information is being collected and will be laid on the Table of the House.

नये सीमेंट कारखानों की स्थापना

4441. श्री ओंकार लाल बेरबा : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बूंदी में एक सीमेंट कारखाने के लिये किसी गैर-सरकारी फर्म को लाइसेन्स दिया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश में सीमेंट के तीन और कारखानों के लगाये जाने की संभावना है;

(ग) यदि हाँ, तो ये कारखाने कहाँ-कहाँ लगाये जाने की संभावना है; और

(घ) बूंदी में सीमेंट कारखाने के कब तक लगाये जाने की संभावना है?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (घ). राजस्थान के बूंदी में 20, 000 मी० टन वार्षिक क्षमता वाला सीमेंट का एक कारखाना स्थापित करने के बारे में एक प्राइवेट पार्टी की योजना (बिड़ला समूह की) के लिये नवम्बर, 1965 में स्वीकृत दी गई थी और एक आशय-पत्र भी जारी किया गया था। उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन सीमेंट उद्योग लाइसेन्स देने सम्बन्धी उप-बन्धों से मुक्त कर दिया गया है, और सीमेंट का कारखाना स्थापित करने के लिए लाइसेन्स प्राप्त करना किसी के लिए अब आवश्यक नहीं रह गया है। बताया जाता है कि पार्टी ने विस्तार में चूने के पत्थर की खुदाई का कार्य पूरा कर लिया है और वित्तीय संस्थाओं को ऋण के लिए आवेदन-पत्र भेज दिए हैं। संयंत्र तथा मशीनों के सम्भरण के लिए मशीन निर्माता को एक अस्थायी आर्डर भी दे दिया गया है। इसी बीच रेल मंत्रालय ने सूचित किया है कि प्रस्तावित कोट-बूंदी-चित्तौड़गढ़ लाइन बहुत ही अलाभप्रद होगी और इसलिए कोटा से बूंदी तथा चित्तौड़गढ़ रेलवे लाइन बनाने का प्रस्ताव फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने अब सूचित किया है कि जब तक रेलवे लाइन का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो जाता तब तक के लिए बूंदी में सीमेंट का कारखाना स्थापित करने का विचार स्थगित किया जाता है।

(ख) और (ग). देश में चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में सीमेंट के निम्नलिखित कारखाने स्थापित किए जाने की संभावना है :-

स्थान	क्षमता (मी०टन) लाख में
1. रामागुण्डम (आंध्र प्रदेश)	2
2. मंघार (मध्य प्रदेश)	2
3. कहर (मद्रास)	4
4. अलंगुलम (मद्रास)	4
5. धुगुस (महाराष्ट्र)	4
6. बाडी (मैसूर)	4
7. कुरकुंता (सेरम) (मैसूर)	2
8. उदयपुर (राजस्थान)	2
9. दल्ला (उत्तर प्रदेश)	4

EXPORT OF SPORTS GOODS TO
U. S. S. R.

4442. SHRI RAJDEO SINGH : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) the countries importing sports goods from India and the amount of annual purchases, country-wise ;

(b) whether it is a fact that the U.S.S.R. has been a traditional purchaser of sports goods from India ; and

(c) if so, whether she has diverted the purchase order to Pakistan and this country has got no order this year ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : (a) A statement showing of exports of sports goods to major countries of import during the last 3 years is laid on the Table of the House [Placed in Library. See No. LT-513/68].

(b) U.S.S.R. showed interest in Indian Sports Goods for the first time in 1963. Exports to that country have been as follows :

Year	Value in lakh Rs.
1963	4.04
1964	0.15
1965	7.90
1966	5.40
1967	—

(c) No information is available about U.S.S.R. having diverted their purchase of sports goods to Pakistan.

IMPROVEMENT OF FREQUENCY AND
SPEED OF TRAINS ON SUB-URBAN
SECTION IN DELHI AREA

4443. SHRI RAJDEO SINGH : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the steps which are proposed to be taken by the Railways to improve the frequency and speed on each suburban section of Northern Railway in Delhi area ;

(b) whether it is a fact that on some sections the average time taken in a journey of 15 K. M. from Sarojini Nagar to Delhi Main is more than one hour; and

(c) if so, the steps proposed to be taken in the matter ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA) : (a) In order to increase the frequency of services on the suburban sections of Northern Railway in Delhi area, four additional pairs of trains between New Delhi and Ghaziabad, New Delhi & Hapur, New Delhi & Ballabgarh and Delhi & Garhi Harsaru have been introduced from 1-12-1967. Within the limitations of availability of resources, further increases are contemplated.

Suburban trains in Delhi area are booked to run at the permissible speeds consistent with the existing modes of tracks and traction and the minimum halts necessary for the convenience of commuters, leaving no scope for speeding up at present.

(b) Yes. The journey time of over one hour includes time for seven stoppages en route and Engineering time for development works.

(c) As and when improved facilities become available, the question of higher speeds will be duly considered.

CONTAINER SERVICE ON RAILWAYS

4444. SHRI RAJDEO SINGH : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the expenditure incurred on account of the container service introduced on the Indian Railways so far ; and

(b) the income derived from the container service during the above period ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA) : (a) The total working expenses incurred upto February 29, 1968 on three container services since introduced on the Indian Railways is about Rs. 8,22,701—.

Expenses incurred for creation of assets, e.g., containers and flats, road vehicles, garages etc., for all the three services works to about Rs. 28,90,814/-.

(b) The income derived by the railways from the three container services works to about Rs. 11,33,395/- upto February 29, 1960.

MODE OF TRADE WITH U.S.S.R.

4445. **SHRI S. K. TAPURIAH :** Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether the pattern and procedure of trade between the U.S.S.R. and India has undergone any change in the new arrangement for 1968; and

(b) if so, what are the salient changes and the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : (a) and (b). No new trade agreement has been signed between Indian and U.S.S.R. recently as the current agreement signed on 10-6-68 is valid upto 31st December, 1970. Only the commodities to be exchanged between the two countries during 1968 was finalised on 26-12-1967. Hence there has been no change in the pattern and procedure of trade between India and U.S.S.R. during 1968.

ENGINEERING INDUSTRY IN WEST BENGAL

4446. **SHRI S. K. TAPURIAH :** Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of West Bengal submitted a report to the Central Government with regard to the crisis of engineering industry in West Bengal ;

(b) whether the report has indicated lack of orders from the Centre as one of the main causes of such crisis; and

(c) if so, the steps taken to meet the crisis ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (a) and (b). In response to a request from the Government of India, the Government of West Bengal submitted a report in the matter indicating the broad reasons for the recession in the Engineering Industries. These included lack of orders, not so much from Central Government Organisations as general feature of the market, lack of avenues for exports, inadequacy of credit facilities and general price of food and other consumer goods.

(c) The steps already taken by the Government of India to mitigate the effect of recession include the review of the various developmental programmes with a view to reviving the demand for capital goods to the extent possible; encouraging diversification in the manufacturing programmes of the affected industries, emphasis on the development of regular export markets through stronger marketing structures both for the public and private sectors; banning of imports to the extent the indigenous capacity can meet the requirements, including a review of imports already authorised but not irrevocably committed, and announcement of liberalised credit policy, including the recent announcement about reduction in the Bank rate.

RAILWAY LINES FROM DUM DUM TO PRINCEP GHAT AND DUM DUM TO BALLYGUNJ

4447. **SHRI B. K. MODAK :**
SHRI K. M. ABRAHAM :
SHRI BHAGBAN DAS :
SHRI K. ANIRUDHAN :

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the progress made in the survey of two railway lines from Dum Dum to Princep Ghat and another from Dum Dum to Ballygunj through salt lake area in Calcutta ;

(b) if so, when the survey is likely to be completed;

(c) whether this project will be included in the Fourth Plan ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA) : (a) About 75 %.

(b) By September, 1968.

(c) and (d). A decision regarding inclusion of this project in the Fourth Plan will be taken by the Planning Commission after the survey is completed and the reports are scrutinised by the Metropolitan Transport Team of the Planning Commission under whose age is the survey is being carried out.

EMPLOYEES OF ELECTRIFICATION RAILWAY PROJECT, CALCUTTA

4448. **SHRI B. K. MODAK :**
SHRI BHAGABAN DAS :
SHRI MOHAMMAD ISMAIL :
SHRI GANESH GHOSH :

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the employees of the Railway Electrification Project, Calcutta staged mass "stay" in the office of the Chief Administrative Officer, Calcutta on the 12th February, 1968;

(b) if so, their demands; and

(c) the steps taken by Government to settle them ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA) : (a) and (b). It is understood that some of the Ministerial staff of the Railway Electrification Project offered 'Stay-in-Strike' in the office of the Chief Administrative Officer, R. E., Calcutta on 12-2-68 to Protest against the orders re-organising the set-up of the Railway Electrification Organisation.

(c) No action is proposed.

AYHA ATTACHED TO 1ST CLASS LADIES WAITING ROOM AT DURGAPUR STATION

4449. **SHRI B. K. MODAK :**
SHRI BHAGABAN DAS :
SHRI MOHAMMAD ISMAIL :
SHRI GANESH GHOSH :

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an Ayha used to be attached to 1st class ladies waiting room at Durgapur Station ;

(b) whether it is also a fact that abolition of the post of Ayha since February, 1968, has caused inconvenience to lady passengers ; and

(c) if so, the reason for abolishing the post ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA) : (a) Yes.

(b) and (c). It was found that the Ladies Waiting Room was seldom being used by passengers and the post of Ayha was, therefore, abolished on grounds of economy. The bearer of the Gents Waiting Room which is located nearby looks after the Ladies Waiting Room also. No complaint of inconvenience has been received on this score so far.

TEXTILE CORPORATION

4450. **SHRI K. M. ABRAHAM :**
SHRI K. ANIRUDHAN :
SHRI UMANATH :
SHRI K. RAMANI :

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) the progress made in the formation of the Textile Corporation ; and

(b) when it is likely to start functioning ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : (a) and (b). It has been decided to establish the Textile Corporation. The formalities regarding its registration are now being attended to and the Corporation is expected to be established in about a month's time.

MODEL WOOLLEN MILLS, BOMBAY

4451. **SHRI K. M. ABRAHAM :**
SHRI NAMBIAR :
SHRI E. K. NAYANAR :
SHRI UMANATH :

Will the Minister of COMMERCE be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 8 on the 13th February, 1968 regarding Model Woollen Mills, Bombay and state :

(a) whether Government have since examined the C.B.I. report ;

(b) if so, details thereof and the decision taken in the matter; and

(c) if not, the reasons for the delay and when its examination is likely to be completed ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : (a) to (c). The matter is still under examination.

IMPORT LICENCES FOR DEEP SEA FISHING TRAWLERS

4458. **SHRI A. K. GOPALAN :**
SHRI K. ANIRUDHAN :
SHRIMATI SUSHEELA GOPALAN :

Will the Minister of COMMERCE be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 83 on the 13th February, 1968 and state ;

(a) whether Government have since considered the representation received from the Indian Sea-Food Exporters Association, Cochin regarding the grant of import licences for deep sea fishing trawlers ;

(b) if so, the decision taken thereon; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : (a) to (c). The question of import of trawlers for meeting the requirement of the industry including the requirement of the exporting units about which the representation has been made is under review of the Government.

CANNANORE CO-OPERATIVE SPINNING MILL

4453. **SHRI A. K. GOPALAN**
SHRI P. GOPALAN :

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether Government propose to develop the Cannanore Co-operative Spinning Mill;

(b) if so, the details thereof ;

(c) the total amount allocated therefor ; and

(d) when the work is likely to start ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : (a) to (d). The Kerala Government propose to enhance the present capacity of this mill to Rs. 25,000 spindles for which it holds a licence in two stages of about 6000 spindles each. The cost of the first phase is estimated to be Rs. 34.77 lakhs and it is expected to be implemented shortly. The State Government have already sanctioned loans to the extent of Rs. 100 lakhs for this mill.

REGIONAL TRADING CORPORATION IN KERALA

4454. **SHRI A. K. GOPALAN :**
SHRIMATI SUSHEELA GOPALAN :
SHRI P. GOPALAN :

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Kerala Government have decided to set up a Regional Trading Corporation on the pattern of the State Trading Corporation ;

(b) if so, whether Government have approved the proposal ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : (a) Government have been informed that the State Government proposes to set up a Commercial Corporation.

(b) No proposal has been received by Government in this regard.

(c) Does not arise.

IMPORT LICENCES TO M/s. SARABHAI MARCK OF BARODA

4455. **SHRI NAMBIAR :**
SHRI SATYA NARAIN SINGH:
SHRI E. K. NAYANAR
SHRI P. RAMAMURTI :
SHRI GEORGE FERNANDES:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 9 on the 13th February, 1968 and state :

(a) whether the investigations into the allegations for the misuse of import licences by M/s. Sarabhai Marck of Baroda have since been completed ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the action taken thereon ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

M/s. COOPER ALLEN Co.

4456. SHRI SATYA NARAIN SINGH :

SHRI P. RAMAMURTI :

SHRI GANESH GHOSH :

SHRI K. RAMANI :

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the State Trading Corporation have decided to purchase M/s. Cooper Allen Co. Ltd., Kanpur; and

(b) if so, the terms and conditions of the deal ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : (a) and (b). A communication has been received from the Government of Uttar Pradesh suggesting that the S.T.C. should take over Cooper Allen Company Limited, Kanpur, and run it under its management. The matter is under consideration of the Government in consultation with the Corporation.

DEATH OF A WORKER IN THE KHETRI COPPER MINES

4457. SHRI SATYA NARAIN SINGH:

SHRI C. K. CHAKRAPANI :

SHRI K. RAMANI :

Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a worker employed in Khetri Copper Mines died in an accident on the 31st January, 1968 ;

(b) if so, the circumstances under which he died ;

(c) whether the Khetri Mines workers demonstrated on the 1st February, 1968 demanding suspension of the doctors for refusing to attend to the worker ; and

(d) if so, the action taken by the authorities in the matter ?

THE MINISTER OF STEEL, MINES AND METALS (DR. CHANNA REDDY): (a) and (b). A driver of the workshop of Khetri Copper Project was standing in front of the truck and was sandwiched between the buffers of the truck and the school bus at 2.15 P.M. on 31st January, 1968. He was immediately removed to the Hospital and after medical aid, was sent along with the compounder to Pilani Hospital in an Ambulance as the injury involved major operations. He expired at Pilani Hospital at about 5 A. M. next day, the 1st February, 1968.

(c) A group of workers returning after cremation of the deceased assaulted two doctors of the Project Hospital and later surrounded the Hospital building. They demanded the suspension of the doctors alleging that the medical attention to the deceased was inadequate.

(d) The project authorities have requested the State Government to depute a Doctor to conduct an inquiry into the allegation about the inadequate medical attention paid to the deceased. The Police have also investigated the case regarding assaults on doctors and rioting etc. and have challaned 12 persons.

COOPERATIVE SPINNING MILL IN KERALA

4458. SHRI K. ANIRUDHAN :

SHRIMATI SUSHEELA GOPALAN :

SHRI P. GOPALAN

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether Government propose to start two cooperative spinning Mills in Kerala ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the total amount allocated for these mills ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : (a) and (b). Two spinning mills of 25,000 spindles each were allocated for being set up in the Co-operative sector in the Kerala State. The State Government propose to set up one of these mills at Trivandrum through the Handloom Apex Society and the other at Kozhikode through a Cooperative Society to be formed. The proposal to set up the mill at Trivandrum is being implemented.

(c) As ascertained from the Kerala Government no funds have been allocated.

COKING COAL

4459. **SHRI N. K. SOMANI :** Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the producers of coking coal are losing on sand-stowing because stowing subsidies are much below the present cost ;

(b) if so, the extent of loss; and

(c) the steps envisaged to encourage stowing for efficient mining of coking coal which is locked up in pillars and which is urgently needed by the Steel Plants ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL, MINES AND METALS (SHRI P. C. SETHI) : (a) to (c). There have been some representations on the inadequacy of subsidies. The whole question has been remitted for a detailed study to a Study Group. On receipt of the report of the Study Group, it will be examined as to the extent to which the scheme or subsidies need be liberalized or rationalized. The Coal Board has, however, undertaken an ambitious scheme of transportation of sand in large quantities for supply to collieries for stowing.

MINING LEASE FOR CHROMITE IN ORISSA

4460. **SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI :** Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to state :

(a) whether any mining lease has been granted for chromite in Orissa in 1966-67, 1967-68 and 1968-69 ;

(b) if so, to whom and where ;

(c) whether Chromite ore bearing areas were preserved for exploitation in the public sector in Orissa; and

(d) if so, the reasons for the change ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL, MINES AND METALS (SHRI P. C. SETHI) : (a) to (d): The required information had been called for from the Government of Orissa and will be placed on the Table of the House when received.

IMPORT OF PRESS-BRAKES BY U.S.A.

4461. **SHRID. AMAT :** Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether U.S.A. have placed any orders for importing press-breaks from the Hindustan Machine Tools, Hyderabad; and

(b) if so, the number of press-brake to be exported and the value thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : (a) and (b). Yes, Sir. H. M. T. have received an order from U.S.A. for the supply of Press Brakes. The value of the order is about Rs. 10 lakhs.

GYPSUM DEPOSITS IN RAJASTHAN

4462. **SHRI MAHANT DIGVIJAI NATH :** Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Gypsum deposits have been found in the Jaisalmer district of Rajasthan ;

(b) if so, whether digging has started in the area ;

(c) the annual expected output ; and

(d) whether Government propose to export Gypsum; and if so, the likely foreign exchange to be earned therefrom ?

THE MINISTER OF STEEL, MINES AND METALS (DR. CHANNA REDDY) : (a) Yes, Sir.

(b) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

EMPLOYEES OF SIGNAL AND TELECOMMUNICATIONS BRANCH

4463. SHRI K. K. NAYAR : Will the MINISTER OF RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the employees of the Signal and Telecommunication Branch called for emergency duty beyond their regulated hours to attend on failure or malfunction of signal and telecommunication equipment are neither paid extra remuneration for overtime work nor compensation in any other way either through extra leave or extra rest; and

(b) if so, the steps Government propose to take in the matter ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA) : (a) and (b). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

UNIFORMS FOR RAILWAYS SIGNAL AND TELECOMMUNICATION STAFF

3464. SHRI K. K. NAYAR : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Signal and Telecommunication field staff are not provided with any kind of uniforms where Train Examiners, Yard Foreman, Electricians Cabin Staff etc. have been provided uniforms ;

(b) if so, the reasons this therefor; and

(c) the action Government propose to take in the matter ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA) : (a) No.

(b) and (c). Do not arise.

ALL INDIA RAILWAY MINISTERIAL STAFF ASSOCIATION

4465. SHRI NANJA GOWDER : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the All India Railway Ministerial Staff Association has requested the Railway Board to change the designation of clerk as "Assistant"; and

(b) if so, the action taken thereon ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA) : (a) Yes; Sir.

(b) Government do not find any justification to accede to this request.

MAJOR INDUSTRIAL PROJECTS IN MADRAS

4466. SHRI NANJA GOWDER : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is fact that the Madras Government have requested for the establishment of some major industrial projects for the manufacture of (i) Electronic equipment, (ii) heavy plates and vessels, and (iii) second unit of the Indian Telephone Industries, Bangalore; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (a) and (b). Requests had been received from the Madras Government for the establishment of projects for the manufacture of Heavy Plates and Vessels, and the second unit of the Indian Telephone Industries in Madras. No request has however been received in regard to the project for the manufacture of Electronic Equipment.

A decision had already been taken about the setting up of the first Heavy Plates and Vessels Projects at Vishakhapatnam. Government considered the possibility of setting up the second Heavy Plates and Vessels Project at Madras, but it has since been decided not to implement this Project for the time being.

No decision has yet been taken about the location of second Unit of the Indian Telephone Industries for the manufacture of long distance transmission equipment.

इस्पात का निर्यात

4467. श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात के निर्यात में वृद्धि होने की सम्भावना है क्योंकि बहुत से देश इसके लिये क्रयादेश देने को तैयार हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन देशों के नाम क्या हैं ; और

(ग) उन वस्तुओं का व्यौरा क्या जिनके निर्यात के बारे में पेशकश आई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (श्री चन्ना रेड्डी) : (क) से (ग). इस्पात के निर्यात में वर्षानुवर्ष वृद्धि विदेशों से स्पर्धा मूल्यों पर क्रयादेश प्राप्त करने के लिए भारतीय इस्पात निर्यातकों के साधारण और हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के विशेष प्रयत्नों के कारण हुई है। हाल में सोवियत रूस को 6 लाख टन इस्पात निर्यात करने का एक बड़ा आर्डर लिया गया है। निर्यात वर्ष 1968, 1969 और 1970 में प्रतिवर्ष 2 लाख टन के हिसाब से किया जाएगा। वर्ष 1968 में जो माल निर्यात किया जाएगा उसमें बीम, चैनल और ऐंगल शामिल हैं। आगामी वर्षों में निर्यात किये जाने वाले इस्पात के बारे में बाद में निर्णय किया जाएगा।

HINDUSTAN STEEL LTD.

4468. SHRI K. LAKKAPPA :
SHRI S. M. KRISHNA :

Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to state :

(a) whether it is fact that the many foreign countries which had placed orders with Hindustan Steel Ltd. have cancelled their orders and placed their orders with other private concerns ; and

(b) if so, the reasons therefor and the names of such countries ?

THE MINISTER OF STEEL, MINES AND METALS (DR. CHANNA REDDY):
(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

GOVERNMENT OWNED INDUSTRIES IN MYSORE

4469. SHRI K. LAKKAPPA :
SHRI S. M. KRISHNA :

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) Whether Government are aware that many Government owned Industries in Mysore are being negotiated by private industrialists; and

(b) if so, the names of the industrialists and the details of the negotiations?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (a) and (b). The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

TRAIN EXAMINERS ON THE RAILWAYS

4470. SHRI M. L. SONDHI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the orders of the Railways Board concerning the Train Examiners were discriminatory ;

(b) where several representations against these orders have been turned down ; and

(c) whether on a writ petition, the Supreme Court quashed the above orders and if so, why the orders have not been withdrawn ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA) : (a) to (c). The Supreme Court have given a judgment that the instructions issued by the Ministry of Railways regarding promotions of erstwhile Apprentice Train Examiners to the grade Rs. 205-280, are *ultra vires* of the Constitution. The details of the implementation of the Supreme Court's judgment are being worked out and necessary instructions will be issued.

LOANS GIVEN TO MINISTERS OF MANIPUR FOR PURCHASE OF CARS

4471. SHRI M. MEGHACHANDRA : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to refer to the statement laid on

the 1st March, 1968 in fulfilment of the assurance given on the 15th December, 1967 in reply to Unstarred Question No. 4576 and state :

(a) whether the ex-Ministers who took car advances have since repaid their loan with interest ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if the reply to part (a) above is in the negative the steps taken to realise the same ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (a) to (c). The required information is being collected and will be laid on the Table of the House.

EXPORT AND IMPORT OF LIQUORS

4472. **SHRI K. SURYANARAYANA :** Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) the number of countries to which Indian liquors are being exported and imported from and the quantities thereof during the last three years ; and

(b) the amount of foreign exchange earned and spent thereby ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : (a) and (b). Statements are laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See No. LT-514/68*].

EARNINGS TO RAILWAYS ON MANGO CONSIGNMENTS

4473. **SHRI B. N. KUREEL :** Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the total earnings of the Railways on the mango-consignment on the Western and Southern Railways during the period from 1964-65 to 1966-67 ;

(b) the total amount of claims paid to the parties on mango-consignments during the above period ;

(c) the total amount due to be paid by the Railways against such claims for 1967-68 ; and

(d) the net profit to the Western and Southern Railways by the mango traffic ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA) : (a) Figures of earnings from mango consignments are not separately maintained. To extract them from the original station records would be a stupendous task. Besides, records for a part of this period would not now be available. It is regretted, therefore, that the information cannot be supplied.

(b) and (c). Figures of claims paid are maintained in certain broad categories of commodity groups. Separate figures in respect of consignments of mangoes are not available. It would not be practicable to extract the information from individual claim files, which number some six lakhs a year. It is regretted, therefore, that the information asked for cannot be supplied.

In view of what is stated in answer to parts (a), (b) and (c), this information cannot be supplied.

ERADICATION OF CORRUPTION ON RAILWAYS

4474. **SHRI B. N. KUREEL :** Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the present strength of the Vigilance Department created to check corruption on the Railways ;

(b) the procedure for the appointment of staff of this Department ; and

(c) how far this Department has been able to stop the corruption on the Railways ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA) : (a) The total strength of the Vigilance Organisation on the Indian Railways as on 31-12-1967 was as follows :

Gazetted	60
Non-Gazetted	755

(b) All Gazetted and investigational staff for the Vigilance Organisation of the Indian Railways are drafted from the various departments of the Railways, such as Traffic, Engineering, Stores, etc. as well as from the State Police and Administrative, cadres, on a tenure basis.

(c) It may not be possible to assess with any degree of accuracy the extent to which corruption on the Indian Railways has been eradicated as a result of Vigilance activities.

EARNING TO RAILWAYS ON STONE CONSIGNMENTS

4475. SHRI B. N. KUREEL : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the total earnings of the Railways on the stone consignments during the years 1964-65, 1965-66, 1966-67 and 1967-68;

(b) the total amount of claims paid on the stone consignments by the Indian Railways during the above period ; and

(c) the total amount of claims paid by the Railways on Mangalore tiles during the above period ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA) : (a) The total earnings of the Railways from stone consignments, including marble, during the years 1964-65, 1965-66, 1966-67 and the first half of 1967-68 are shown below :

1964-65	..	7.77 crores
1965-66	...	8.46 crores
1966-67	..	10.42 crores
1967-68	...	4.48 crores

(April to September, 1967).

(b) and (c). Separate figures are not maintained in respect of claims paid against consignments of stone and Mangalore tiles. To extract the information, a reference would have to be made to individual files, which number more than five lakhs a year. It is regretted, therefore, that the information asked for cannot be supplied.

PROCUREMENT OF SHOES BY S.T.C.

4476. SHRI VIDYA DHAR BAJPAI : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the State Trading Corporation has opened an office at Calcutta from where it procures 10,000 pairs of shoes per year ;

(b) whether the procurement from Ludhiana and Karnal was 70,000 pairs approximately during 1967 ; and

(c) if so, the reasons for not opening offices at Karnal and Ludhiana respectively ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : (a) STC's regional office in Calcutta looks after the procurement of footwear and leather components for exports to various countries. In 1967 STC placed order in Calcutta for 21,000 pairs of shoes and 1,82,000 pairs of cowboy upper leathers.

(b) Orders placed on suppliers in Ludhiana and Karnal in 1967 were of the order of 7,320 and 33,760 pairs respectively.

(c) Procurement of shoes from Karnal and Ludhiana is made through State Export Corporation and State Trading Corporation does not consider it necessary to open separate office for this purpose. The Corporation have posted a senior Inspector in these areas.

PRICES OF SHOES CHARGED BY S. T. C.

4477. SHRI VIDYA DHAR BAJPAI : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) Whether the State Trading Corporation charged commission from Rs. 10 to Rs. 15 per pair of shoes exported to U.S.S.R. and Bulgaria during the period from 1956 to 1967;

(b) if so, the reasons thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

बांदा जंक्शन पर पूछताछ कार्यालय

4478. श्री जगेश्वर यादव : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बांदा जंक्शन पर कोई पूछताछ कार्यालय नहीं है, और

(ख) यदि हां, तो वहां पर ऐसा कार्यालय कब तक स्थापित हो जायेगा ?

रेलवे मंत्री (चे० मु० पुनाचा) : (क) बांदा में अलग से कोई पूछताछ कार्यालय नहीं है। लेकिन स्टेशन पर सार्वजनिक टेलीफोनो की व्यवस्था है और जनता की पूछताछ का उत्तर स्टेशन के कर्मचारियों द्वारा दिया जाता है।

(ख) अलग से पूछताछ कार्यालय बनाने का कोई विचार नहीं है।

लखनऊ-बाँदा एक्सप्रेस तथा कानपुर-बाँदा यात्री गाड़ियां

4479. श्री जगेश्वर यादव : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे उत्तर में लखनऊ-बांदा एक्सप्रेस और कानपुर-बांदा सवारी गाड़ियां, जो क्रमशः लखनऊ और कानपुर से चलती हैं। इन स्टेशनों से प्रतिदिन देरी से चलती हैं, जिसके परिणामस्वरूप इन गाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्री मध्य रेलवे में झांसी-मानिकपुर सैक्शन पर चलने वाली गाड़ियां नहीं पकड़ पाते; और

(ख) यदि हां, तो इस बात के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है कि उपर्युक्त गाड़ियां देरी से न चलें ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं, प्रतिदिन नहीं। सिवाय एक दिन के 522 अप/523 डाउन मानिकपुर झांसी सवारी गाड़ियों से सभी दिन मेल हुआ लेकिन 521 डाउन/524 अप गाड़ियों से मेल की स्थिति सन्तोषजनक नहीं रही।

(ख) इस बात पर विशेष निगरानी रखी जाती है कि ये गाड़ियां ठीक समय पर आया-जाया करें और झांसी-मानिकपुर खण्ड में चलने वाली गाड़ियों से मेल लिया करें। चूंकि खतरे की जंजीर खींचने की बहुत अधिक घटनाओं के कारण लखनऊ-बांदा एक्सप्रेस और कानपुर-बांदा सवारी गाड़ियों के समय-पालन पर बहुत बुरा असर पड़ा है, M18LSS(CP)/68-7

इस लिए ऐसी घटनाओं को कम करने के लिए राज्य सरकारों और पुलिस प्राधिकारियों के परामर्श से विशेष उपाय किये जा रहे हैं।

LICENCE FOR IMPORT OF SULPHUR

4480. SHRI N. SHIVAPPA : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether Government have recently issued import licences to certain firms in Bombay for the import of sulphur, ammonia and phosphate to the tune of several crores of rupees ;

(b) whether complaints have been received in this regard ; and

(c) if so, the action taken thereon ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : (a) A statement of import licences issued for import of sulphur is laid on the Table of the House [Placed in Library. See No. LT-515/68]. No licences have been issued for import of ammonia and phosphate to any Bombay firm.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

HASSAN-MANGALORE RAILWAY LINE

4481. SHRI N. SHIVAPPA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the progress made and the amount spent on the construction of the Hassan-Mangalore railway line during 1967 ;

(b) the number of tunnels completed during the above period ; and

(c) the probable date of the completion of the line ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA) : (a) A progress of 8% and 7.5% respectively was achieved on the Mangalore-Panambur link and the main line from Hassan to Mangalore during 1967. The expenditure incurred on the project during 1967-68 (upto February, 1968) is Rs. 96.49 lakhs.

(b) No tunnels have been fully completed during 1967.

(c) Work on this project is being phased to synchronise with the completion of the Mangalore Port project. The link from Mangalore to Panambur Port is expected to be ready by November, 1968.

**PILFERAGE OF COAL FROM RAILWAY
WAGONS**

4482. SHRI N. SHIVAPPA : }
Dr. M. SANTOSHAM : }

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the total number of wagons utilised for carrying coal for the Railways on an average per day;

(b) the total quantity of coal pilfered from the railway wagons on an average per day;

(c) the loss incurred by the Railway Exchequer annually as a result of such pilferage; and

(d) whether any action in this regard has been taken against the Railway officers for their negligence and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA) : (a) 2125 broad gauge wagons daily.

(b) and (c). It is not possible to assess the total quantity of coal pilfered from the wagons on an average per day and to estimate the actual loss suffered by the Railways on this account.

(d) Railway staff are severely taken up when found responsible for negligence in their duties resulting in pilferage of coal which may amount to even dismissal/removal from service.

**DISBANDING OF RAILWAY PROTECTION
FORCE**

4483. SHRI RAMACHANDRA VEE-RAPPA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government are considering the proposal to disband the Railway Protection Force and to assign part of its duties to the State Police Force; and

(b) if so, what would be the saving as a result thereof and when the scheme is likely to be implemented?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA) : (a) No such proposal is under consideration.

(b) Does not arise.

JAPANESE INDUSTRIAL DELEGATION

4484. SHRI RAMACHANDRA VEE-RAPPA : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a Japanese Industrial Delegation visited India in September, 1967; and

(b) If so, the prospects regarding the investment in India by the Japanese Private Sector?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

**HANDICRAFT SALES CENTRE FOR MANIPUR
IN DELHI**

4485. SHRI M. MEGHACHANDRA : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a small plot of land is being allotted by Government, free of cost, for constructing a handicraft Sales Centre for Manipur, in Connaught Place, New Delhi;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, whether the Government of Manipur has made any request in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The Ministry of Works, Housing and Supply have allotted certain emporia plots on Irwin Road to various State Governments. Out of these, it has been tentatively decided to allot one plot to the Government

of Manipur on payment of the usual charges. There is no question of allotting the land free of cost to the Government of Manipur nor has the State Government made such a request.

INDUSTRIES IN MANIPUR.

4486. SHRI M. MEGHACHANDRA: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of types of industries proposed to be set up in Manipur in 1968-69; and

(b) the amount of financial assistance proposed to be given to Manipur during the above period ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) :

(a) The annual plan of Manipur for 1968-69 provides for carrying out studies on the possibilities of starting certain industrial projects in textile, cement and paper. In the small scale sector; various schemes relating to Handlooms, Handicrafts, Sericulture, Small, Village and Khadi Industries will be implemented during the period.

(b) A sum of Rs. 17 lakhs has been tentatively provided for these industries for the year 1968-6-69.

PELLETISATION PLANT AT BAILLADILLA

4487. SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY: Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to state :

(a) whether there is any proposal for the establishment of a Pelletisation Plant at Bailadila; and

(b) if so, the stage at which the proposal stands at present?

THE MINISTER OF STEEL, MINES AND METALS (DR. CHANNA REDDY):

(a) There is a proposal to set up a pelletisation plant to utilise the fines generated during lump ore production at the mine based on Deposit, 14, Bailadila .

(b) Presently feasibility studies on the Bailadila No. 14 deposit fines are in hand by a Japanese firm, who have arranged to have pelletisation tests carried out at the Battle Memorial Institute Laboratories in U. S. A. These tests are currently progressing and a feasibility report is expected by about June this year.

RAILWAY GUARDS

4488. SHRI ISHAQ SAMBHALI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a deputation of M. Ps. met the Minister of State for Railways on the 23rd December, 1967 and discussed the demands of the Railway Guards;

(b) whether it is also a fact that on two occasions, a joint memorandum duly signed by about 50 M.Ps. was submitted to him in this connection; and

(c) if so, the decision taken in the matter?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA) : (a) Yes. A deputation of M.Ps. met him on 22nd December, 1967 .

(b) Yes. Two memoranda, one signed by about 37 M. Ps. and the other by about 34 M. Ps., were received.

(c) A Committee to review the rules and rates of Running Allowance of all categories of Running Staff (including Guards) has been appointed and its report is expected by the end of May, 1968.

EXPORT HOUSES

4489. SHRI S. K. TAPURIAH : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government have recently revised the minimum limit of export turnover from Rs. 10 lakhs to Rs. 25 lakhs for non-traditional products for recognition as Export Houses;

(b) whether for traditional items, the limit has been raised to Rs. 2 crores for the same purpose; and

(c) if so, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir. Under the earlier scheme of recognition as Export Houses, exporters handling only traditional goods were not at all eligible for recognition. The facility has now been extended to them, provided they fulfil a minimum export performance. The question of revision of minimum qualifications in this case, therefore, does not arise.

(c) The scheme of Export Houses has been revised as a normal export promotion measure with a view to make Export Houses more effective in the marketing of products abroad.

EXPORT OF WAGONS TO U.S.S.R.

4490. SHRI D. N. PATODIA : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether production schedules for the supply of 10,000 eight wheeler wagons to U. S. S. R. have been drawn up;

(b) the production targets both for the public and the private sectors;

(c) the names of firms in the private sector and the number of wagons to be manufactured by each of them; and

(d) the estimated annual foreign exchange earning from this deal ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : (a) to (c). Production schedule for the supply of wagons to USSR, the question of allocation of the production to the public and the private sector or the number of wagons to be manufactured are all as yet the subject matter of negotiation. A Russian Railway Delegation which is in India are discussing these details with the various authorities. An Indo-Soviet protocol was signed on 13-3-68 laying down a schedule for the export of 2,000 wagons in 1969-70, to be stepped up in successive years, reaching the figure of 10,000 wagons per year in 1972-73.

(d) It is too early to make an estimate of annual foreign exchange to be earned from this deal.

सागर जिले में केल्साइट निक्षेप

4491. श्री निहाल सिंह : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री 24 नवम्बर, 1967 के आतारंकित प्रश्न संख्या 1643 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सागर जिले में सात मील लम्बी पट्टी में बताये जाने वाले केल्साइट निक्षेपों का पता लगाने के लिये इस बीच कोई सर्वेक्षण दल नियुक्त किया है या नियुक्त करने का विचार है, और

(ख) सर्वेक्षण करने पर अन्य किन निक्षेपों का पता लगा ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) नहीं, महोदय। फिर भी 1967-68 के कार्यक्रम के मौसम में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा सागर जिले का खनिज सर्वेक्षण किया जाना प्रस्तावित है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

VISIT OF SOVIET RAILWAY DELEGATION TO INDIA

4492. SHRI YASHPAL SINGH : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a Soviet Railway Delegation visited India in March, 1968;

(b) whether any negotiations were held with the delegation; and

(c) if so, the outcome thereof ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) A U. S. S. R. Delegation headed by the Vice-Minister of Soviet Railways arrived in India at the end of February 1968 for conducting technical discussions regarding the possibility of import of Railway wagons from India to U.S.S.R. to Soviet design and specification. As a result of discussions, a protocol has been signed on 13-3-68 between the State Trading Corporation and the Mechino-import USSR laying down the procedure to be followed for further negotiations in order to supply wagons to USSR.

**COMMISSION CHARGED BY S.T.C. ON
EXPORT OF SHOES.**

4493. SHRI D. N. PATODIA : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(u) Whether it is a fact that the State Trading Corporation keeps to itself Rs. 10 per pair of shoes as its margin for meeting expenses involved in packing, freight, inspection, development and publicity;

(b) whether the industry has represented that because of this big margin taken by the State Trading Corporation, very little is left to it;

(c) the total amount thus collected annually by the State Trading Corporation; and

(d) the break up of its utilisation ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : (a) No, Sir.

(b) S. T. C.'s fabricators had represented for an increase in the procurement prices payable to them for shoes for shipment to U.S.S.R. The procurement prices were worked out on the same formula as applied in 1967 and are considered workable for the fabricators.

(c) and (d). It is not in the business interest of the S. T. C. to divulge this information.

MYSORE IRON & STEEL WORKS, BHADRAVATI

4494. SHRI J. H. PATEL : Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to state;

(a) the financial position of the Mysore Iron & Steel Works at Bhadravati and whether it is incurring any loss;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether Government propose to order an inquiry into the affairs of the Company ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF STEEL, MINES AND METALS (CHOWDHARY RAM SEWAK) :

(a) Mysore Iron & Steel Ltd. is running at profit.

(b) and (c). Do not arise.

**खादी प्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली
में वस्तुओं की बिक्री**

4495. श्री झा० सुन्दरलाल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी प्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में बेची जाने वाली वस्तुएं कुछ अमान्य संगठनों से खरीदी जाती हैं और वे मनमाने दाम लगाकर, जो बाजार में उन्हीं वस्तुओं के दामों से कई गुना अधिक होते हैं, काफी मुनाफा कमा रहे हैं ;

(ख) क्या इस माल का भारी स्टॉक बिना बिक्री पड़ा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार की क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरंशी) : (क) सरकार को ऐसी खरीदारियों के बारे में जानकारी नहीं है ।

(ख) जी, नहीं :

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

LOOTING OF GOODS TRAIN NEAR NIMIAGHAT STATION

4496. SHRI K. P. SINGH DEO : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a goods train was raided and looted by a mob of miscreants between Bholidih and Nimiaghat stations of Eastern Railway on the 2nd March, 1968;

(b) whether it is also a fact that at the same place, the same train was looted on the 26th February, 1968;

(c) if so, the loss incurred as a result thereof; and

(d) the steps taken by Government in the matter ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA) : (a) and (b).

It is a fact that goods train No. 1173 was stopped by some miscreants between Bholidih and Nimiaghat on 26-2-1968 and again on 2-3-1968 when some villagers with the help of temporary gangmen attempted to commit pilferage but were prevented from doing so by the timely action taken by Railway Protection Force. 6 persons including 2 gangmen were arrested and Government Railway police, Gomoh have registered a case under section 143/379 Indian Penal Code in this connection.

(c) Does not arise.

(d) Railway Protection Force pickets were posted at Bholidih and Nimiaghat Railway Stations. Railway Protection Force Escorts have been provided on goods trains in the affected section.

EXPLOSION OF BOMB ON MUGHAL SARAI STATION

4497. SHRI K. P. SINGH DEO: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a bomb exploded on a platform at Mughalsarai Railway Station on the 7th March, 1968;

(b) if so, the number of the persons injured and the loss incurred as a result thereof;

(c) whether the matter has been investigated; and

(d) if so, result thereof?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA) : (a) and (b). Due to explosion of a cracker, 2 persons are reported to have sustained injuries. No loss of property has however, been reported.

(c) and (d). The case has been registered by Government Railway Police, Mughalsarai on crime No, 95 dated 7-3-68 u/s 5/6 Explosive Substance Act. 2 persons have been arrested so far. The case is still under State Police investigation.

CORRECTION OF ANSWER TO UNSTARRED QUESTION NO. 1295, DATED 20-2-1968 REGARDING ASHOKA PAPERS MILLS LTD.

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): While

replying to Unstarred Question No. 1295 on 20-2-68, I had stated that the Government of Bihar had decided to take over the Ashoka Paper Mills Ltd. This information was based on the earlier information furnished by the State Government. They have now intimated that they have reconsidered their earlier decision and have decided on 13-2-68 that it will not be possible for them to take over the Ashoka Paper Mills.

12.09 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

DEMAND FOR SOVEREIGN NAGALAND BY LEFT COMMUNIST NAGAS

MR. SPEAKER: Shri Madhu Limaye.

SHRI NAMBIAR (Tiruchirappalli) : On a point of order under rule 173.

As I have already pointed out in earlier occasions, this matter is repeatedly coming in when such motions are admitted. The motion calls the attention of the Minister to the demand by 'Left Communist Nagas'. This, by implication, is scandalising a party. There is no such thing as 'Left Communist Nagas' in Nagaland. Why is it that repeatedly such motions containing such a nomenclatures are admitted? I want to ask this question of you. There is no such thing as Left Communist Nagas.

श्री मधु लिमये : इनकी पार्टी का नाम तो कम्युनिस्ट पार्टी (मार्किस्ट है)। There is no such thing as Left Communist Party in Nagaland.

SHRI NAMBIAR: My submission is this, that there is no party of left communists.

SHRI SONAVANE (Pandharpur) : On a point of order.

SHRI NAMBIAR : Rule 173 says that it must be a specific matter. He cannot put it that way. It should not implicate a party which is a legal party in the country. (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Call attention notices came not only from one gentleman, but at least 30. Whether there is a party like that in Nagaland or not, it is not the speaker's job to find out. I have no agency in Nagaland.